मिश्र का जनविद्रोह

I

फरवरी 2011 से जुलाई 2013 के बीच मिश्र ने अल्पकाल में इतिहास का एक चक्र पूरा कर लिया। फरवरी 2011 के पहले भी मिश्र में सैन्य तानाशाही थी और जुलाई 2013 के बाद भी सैन्य तानाशाही है। फरवरी 2011 के पहले देश का शासक होस्नी मुबारक था तो 2013 में देश का वास्तविक शासक जनरल अल सिसी है। ऊपरी तौर पर देखने पर भले ही लगता हो कि मिश्र में कुछ नहीं बदला परन्तु इन दो वर्षों में मिश्र की जनता ने दो राष्ट्रपतियों को पद छोड़ने को मजबूर कर दिया। इन दो वर्षों में मिश्र के समाज में मची उथल-पुथल में हजारों लोगों की जानें चली गयीं और लाखों लोगों को अपने जीवन में अनेकों जुल्म सहने पड़े। मिश्र अब पहले जैसा मिश्र नहीं रहा।

2011 में जिन अरब देशों में 'बसन्त' आया वहां अभी भी उस बसन्त का इन्तजार है जो आम लोगों के जीवन को गुलजार कर सके। सच तो यह है कि इन देशों में जिन भौतिक कारणों ने विद्रोह की जमीन तैयार की थी वे आज भी वैसे ही हैं। और उससे भी बढ़कर, पिछले दो वर्षों में ये समाज पहले से भी ज्यादा उस जगह पर खड़े हो गये हैं जहां नये विद्रोह भविष्य में जन्म ले सकते हैं। जिन देशों में जनविद्रोह को कुचला न जा सका वहां संसदीय लोकतंत्र, जो पूंजीवादी तानाशाही का सबसे अच्छा रूप है, अभी तक स्थापित और स्थिर नहीं हो सका है। फौजी तानाशाही का स्थान लेने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे धार्मिक फासिस्ट तानाशाहों ने साम्राज्यवाद के सहयोग से ट्यूनीशिया और मिश्र में जो कामयाबी हासिल की थी उस पर इतनी जल्दी ग्रहण लग जायेगा ऐसा इनमें से किसी ने नहीं सोचा था। जनविद्रोह के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा का असर ऐसा है कि शासक वर्ग की हर पार्टी, हर चरित्र उसकी आंच में झुलसा जा रहा है। मिश्र में होस्नी मुबारक, मोहम्मद मुर्सी के बाद अब अल सिसी अपनी नियति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बसन्त का वज्रनाद सबसे अधिक मिश्र में ही हुआ था और उसकी अनुगूंज अभी तक वहां सुनाई दे रही है। अल सिसी की सरकार के हर कदम को संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। मिश्र के समाज में यह चर्चा आम है कि 'मुबारक के बगैर मुबारकवाद की वापसी हो रही है' । अल सिसी मिश्र का नेपोलियन बोनापार्ट बनना चाहता है।

इस लेख में मिश्र के जन विद्रोह के चरित्र, कारण व भविष्य के बारे में विभिन्न आयामों से विचार किया गया है। इस लेख को इस पत्रिका में पूर्व में विश्व आर्थिक संकट, वैश्विक खाद्य संकट और खासकर अरब विद्रोह से सम्बन्धित लेखों की कड़ी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पूर्व के लेखों में कुछ तथ्यात्मक भूलें थीं जिन्हें यहां पर ठीक कर लिया गया है। मिश्र में जन विद्रोह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चरित्र और उसके राजनीतिक अर्थशास्त्र, विभिन्न वर्गों के साथ साम्राज्यवाद की इस विद्रोह के दौरान भूमिका, मिश्र के भविष्य और इस विद्रोह से सर्वहारा वर्ग के लिए निकलने वाले सबक की चर्चा करने से पहले विद्रोह के अब तक के घटनाक्रम पर एक निगाह डाल लें।

II

राजनैतिक घटनाक्रम

मिश्र में पिछले तीन वर्षों के घटनाक्रम को प्रमुख तीन घटनाओं के आधार पर समझा जा सकता है। मुबारक का पतन, मुर्सी का एक वर्ष का शासन और सैन्य तानाशाही की पुनर्स्थापना। तीनों घटनाओं के पीछे एक व्यापक जनउभार था। तीनों ही घटनाओं में जन को वह अभीष्ट हासिल नहीं हो सका जिसके लिए वे संघर्षरत थे। जन समुदाय के खिलाफ एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रचे जाते रहे और हर बार नये षड्यंत्रकारी के सत्ता हासिल करते ही क्रांति के सम्पन्न हो जाने की घोषणा की जाती रही। अमेरिकी साम्राज्यवादी होस्नी मुबारक के पतन के तुरन्त बाद 'क्रांति' की बधाई देने काहिरा जा पहुंचे और जनसमुदाय से अपील करने लगे कि अब उनका काम समाप्त हुआ, कि अब उन लोगों को काम करने दें जो उनके हितों का सबसे अच्छा ध्यान रख रहे हैं। आम जन समुदाय खासकर मजदूर, युवा और स्त्रियां संघर्ष के मैदान को और उसके प्रतीक स्थल तहरीर चौक को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे और वे लगातार जमे रहे। मुर्सी के शासन काल में भी ऐसा ही हुआ, अब अल सिसी ने आम जनसमुदाय तहरीर चौक में जमा ही न हो पाये इसके लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। आज तहरीर चौक सेना के हवाले है। सेना आज तथाकथित रूप से मिश्र की क्रांति की सबसे बड़ी रक्षक है। यह वही सेना है जिसके दम पर होस्नी मुबारक ने लगभग तीस साल क्रूरतापूर्वक शासन किया था। यह वही सेना है जो पहले मुबारक, फिर मुर्सी और अब अल-सिसी के पीछे खड़ी है। और यह भी कम मजेदार नहीं है कि होस्नी मुबारक ने अपने शासन काल में ईखवान (मुस्लिम ब्रदरहुड) को पाला-पोसा और उसके मुर्सी ने इसके बाद शासन संभाला और मुर्सी ने ही अपने शासन काल में ही अब्दुला फतेह अल-सिसी को सैन्य प्रमुख बनाया था। मुर्सी के समय मुबारक जेल में थे अब सिसी के समय मुर्सी जेल में हैं। और जहां तक मजदूर और आम जन समुदाय का प्रश्न है वे मुबारक के पतन के ठीक पहले भी सड़कों में थे, वे मुर्सी के शासन के एक वर्ष के दौरान भी सड़कों पर थे और अब अल सिसी नये 'प्रोटेस्ट लॉ' के जरिये उन्हें सड़कों से दूर रखने की कोशिश में लगा है।

उपरोक्त के साथ एक बात और गौर करने की है। मुबारक के खिलाफ भी शासक वर्ग का एक हिस्सा सड़कों पर था, मुर्सी के खिलाफ भी शासक वर्ग का एक हिस्सा सड़कों पर जनता के ऊपर अपने नेतृत्व को थोप रहा था और आज अल सिसी के खिलाफ भी शासक वर्ग का एक हिस्सा सड़कों पर है। यानी मिश्र के शासक वर्ग के विभिन्न धड़ों के बीच के अंतरर्विरोध अत्यन्त तीखे हैं और फिलवक्त वह अपने अंतरर्विरोधों को हल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पर्दे के पीछे सुलह-समझौते की तेजी से कोशिशें हो रही हैं पर हर गुट अभी अपने हितों को निष्ठुर ढंग से आगे बढ़ा रहा है। अल-सिसी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह काम करना चाहता है परन्तु समय जल्दी ही साबित कर सकता है कि वह पहला तो क्या दूसरा नेपोलियन भी नहीं बन पाया। इस वक्त अल-सिसी को सेना और मिश्र के शासक वर्ग का बड़ा हिस्सा हीरो के रूप में पेश कर रहे हैं। और सिसी सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वह सब हथकंडे अपना रहे हैं जो एक समय अपने हाथ से सत्ता जाती देख मुबारक अपना रहे थे।

मुबारक का पतन

होस्नी मुबारक ने मिश्र की सत्ता 1981 में तब संभाली थी जब मिश्र के तात्कालीन राष्ट्रपति अनवर अल सादात की हत्या हो गयी थी। अनवर सादात के शासन काल (1970 से 1981) में 18 महीनों को छोड़ दिया जाय तो मिश्र में 1967 में इजरायल के साथ हुये अरब-इजरायल के छः दिवसीय युद्ध के समय से ही आपात कालीन कानून लगे हुए थे। आपातकालीन कानूनों के अनुसार पुलिस के पास असीमित अधिकार थे। संवैधानिक अधिकार नागरिकों को हासिल नहीं थे। मीडिया पर सेंसरशिप कानून सम्मत थी। इन आपातकालीन कानूनों को होस्नी मुबारक की सरकार अलग-अलग कारणों खासकर आतंकवाद के खतरे के नाम पर लगातार लागू किये हुयी थी।

मुबारक के काल में एकदलीय शासन प्रणाली थी और समय-समय पर होने वाले चुनाव (राष्ट्रपति और संसद) एक छल बनकर रह गये थे। मिश्र की सम्पूर्ण सत्ता एक तरह से होस्नी मुबारक और उसकी पार्टी के हाथों में सिमटी हुयी थी। होस्नी मुबारक की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (इस पार्टी की स्थापना 1978 में अनवर सादात ने की थी) को मिश्र के एकाधिकारी पूंजीवादी घरानों का पूर्ण समर्थन हासिल था। मिश्र की सरकार में ऐसे अरबपति धनिकों की भरमार थी। स्वयं होस्नी मुबारक के पास बेइंतहा सम्पत्ति थी।

होस्नी मुबारक के खिलाफ जनाक्रोश वर्षों से खासकर 2005 के बाद से ही इकट्ठा हो रहा था। होस्नी मुबारक का तानाशाहीपूर्ण शासन के खिलाफ बढ़ता आक्रोश और तेज होने लगा जब मुबारक अपने छोटे पुत्र गमाल मुबारक को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने लगे।

2008 में आये विश्व खाद्यान्न संकट के साथ गहराते वैश्विक आर्थिक संकट ने मिश्र की जनता के कष्टों को कई गुना बढ़ा दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ते गुस्से के साथ पुलिस के द्वारा किया जाने वाला दमन लोगों के लिए असहनीय होता जा रहा था। 17 दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में मौहम्मद बौजीजी नामक बेरोजगार युवक के पुलिस के उत्पीड़न के बाद किये गये आत्मदाह के बाद भड़के जनप्रदर्शनों ने तेजी से जनविद्रोह का रूप ले लिया। मिश्र में भी पुलिस का उत्पीड़न वर्षों से एक ज्वलंत मुद्दा था। ट्यूनीशिया की जनता के विद्रोह से प्रेरणा पाकर मिश्र के विभिन्न राजनैतिक समूहों और गैर सरकारी संगठनों ने राष्ट्रीय पुलिस दिवस 25 जनवरी को पुलिसिया दमन के खिलाफ गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन की योजना बनायी। ये प्रदर्शन काहिरा सहित पूरे मिश्र में फूट पड़े। मिश्र की पुलिस दमन पर उतर आयी।

28 जनवरी 2011 'फ्राइडे ऑफ एंगर' या 'क्रोध का दिन' के आयोजन के लिए व्यापक जनगोलबंदी इण्टरनेट के माध्यम से की गई। हजारों लोग काहिरा सहित पूरे देश में सड़कों पर उतर आये। इस विशाल जन समूह को संभालना अब मिश्र की पुलिस के बूते के बाहर था। काहिरा में तहरीर चौक पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। तहरीर चौक में मुबारक समर्थकों और विद्रोहियों के बीच भयानक झड़पें हुयीं। मुबारक पर सत्ता छोड़ने का दबाव बढ़ता चला गया।

2 जनवरी से शुरू हुये विशाल जनप्रदर्शनों की लगातार बढ़ती संख्या ने अंततः 11 फरवरी 2011 को होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़ने को मजबूर कर दिया। मुबारक की तीस वर्षों से अधिक समय से चली आ रही सत्ता जनविद्रोह के आगे तीन हफ्ते भी नहीं टिक सकी। सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली।

मुबारक के सत्ता से हटने का परिणाम यह निकला कि उसकी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी भंग हो गई और उसकी सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति घोषित कर दी गयी। संसद भंग कर दी गई और संविधान को स्थगित कर दिया गया। 31 वर्षों से चली आ रही आपातकाल की स्थिति समाप्त कर दी गयी। नया संविधान बनाने की घोषणा की गई। राजनैतिक पार्टियों के औपचारिक तौर पर गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी। मुबारक और उसके परिवार के सदस्यों पर मुकदमा चलाने की घोषणा की गई। असल में मुबारक ने सत्ता तब ही छोड़ी जब उसने इस बात का लगभग पूरा बंदोबस्त कर लिया कि उसे भविष्य में उन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जायेगा जो उस पर लग रहे थे।

मुबारक के बाद सत्ता संचालन के लिए एस.सी.ए.एफ. (सुप्रीम काउन्सिल ऑफ दि आर्म्ड फोर्सेस) व एस.सी.सी. (सुप्रीम कॉन्स्ट्यूशनल कोर्ट) का गठन उसके सत्ता में रहते ही कर दिया गया। इस काउन्सिल ने जनाक्रोश को ठण्डा करने के लिए मुबारक पर मुकद्मा चलाने और सजा देने की बात कही। सेना फरवरी से मई तक मुबारक पर किसी न किसी तरह से कार्रवाई को टालती रही।

एस.सी.ए.एफ. और राष्ट्राध्यक्ष घोषित किये गये मोहम्मद हस्स तंतवी और उसकी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। एक के बाद दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। भारी जन दबाव के बाद 24 मई 2011 को मुबारक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली बारी आदि के आरोप पर मुकद्मा चलाने की घोषणा की गई। 2 जून 2012 को मुबारक को अपराधी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी।

असल में यह सब मुबारक को एक तरह से सेना के द्वारा संरक्षण प्रदान करने की कोशिश थी। मुर्सी के शासनकाल में मुबारक पर लगाये गये आरोपों पर पुनर्विचार शुरू हुआ और मुर्सी के पतन के बाद जब से सत्ता सेना के हाथों में पुनः आयी है इन्हें दोषमुक्त करने की कोशिशें हो रही हैं। 'मुबारक के बिना मुबारकवाद' के युग की वापसी का जुमला मिश्र में इसी कारण से प्रचलित हो गया है। मुबारक को दोषमुक्त करने की कवायद के साथ उसके समय के बदनाम अधिकारी, राजनेता फिर से नमूदार हो गये हैं। वे एकाधिकारी पूंजीवादी घराने जो मुबारक के शासनकाल में फले-फूले और जो मुर्सी के शासन काल में कुछ हद तक पृष्ठभूमि में चले गये थे अब पुनः समाज में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सुप्रीम कॉन्स्ट्यूशनल कोर्ट एक तरह से मुबारक को दोष मुक्त करने या कम से कम सजा देने की ओर बढ़ रही है।

होस्नी मुबारक के खिलाफ हुए जन विद्रोह में सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस, सेना और मुबारक की गुण्डा वाहिनी द्वारा मारे गये। घायलों की संख्या तो हजारों में है जिसमें से कई जीवन भर के लिए अपंग हो गये हैं। सेना और पुलिस ने इस दौरान हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया। एक अनुमान के अनुसार इस संघर्ष के दौरान मारे गये लोगों की संख्या 864, घायलों की संख्या 6467 व गिरफ्तार लोगों की संख्या 2000 थी (स्रोत : विकीपीडिया)। वर्ष 2011 व 2012 के पहले छः महीनों में लगातार सेना के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे।

एस.सी.ए.एफ. ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद भारी जनदबाव के बीच घोषणा की थी वह छः महीने ही सत्ता संभालेगी। वह संविधान पर जनमत संग्रह, संसदीय चुनाव व भावी राष्ट्रपति का चुनाव करायेगी। राष्ट्रपति चुनाव में वह अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। दिसम्बर 2011-जनवरी 2012 में संसदीय चुनाव व 19 मार्च 2012 को संविधान पर जनमत संग्रह करवाया गया। 30 जून को मुस्लिम ब्रदरहुड के एक नेता मोहम्मद मुर्सी देश के पांचवे राष्ट्रपति बन गये।

मुर्सी का एक वर्षीय शासन

मोहम्मद मुर्सी को मिश्र के पहले ऐसे राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ जिसका चुनाव पूंजीवादी लोकतांत्रिक ढंग से हुआ था। मोहम्मद मुर्सी ने शीघ्र ही पूंजीवादी लोकतंत्र व संवैधानिक प्रक्रियाओं को ऐसी शानदार इज्जत प्रदान की कि वे लोकतांत्रिक ढंग से चुने गये राष्ट्रपति से तानाशाह बन गये। मुबारक के पतन में तो तीस वर्ष से अधिक का समय लगा था परन्तु मोहम्मद मुर्सी अपनी काली करतूतों, बढ़ते जनाक्रोश और शासक वर्ग के बहुत बड़े हिस्से के द्वारा विरोध किये जाने की वजह से एक वर्ष ही शासन कर पाये। मोहम्मद मुर्सी ने एक वर्ष के शासन में एक से बढ़ कर एक प्रतिक्रियावादी कदम उठाये और अगर वह कामयाब हो गये होते तो मिश्र धार्मिक फासिस्ट समाज में तब्दील हो जाता। मिश्र के समाज के बहुत बड़े हिस्से ने मोहम्मद मुर्सी के रूप में गौरव का नहीं कलंक का अनुभव किया। मुर्सी अपने समर्थकों के साथ मिश्र के समाज में अलग-थलग पड़ गये थे। उन्होंने अपने को स्वयं इस स्थिति में पहुंचाया। वे मिश्र के समाज व राजनैतिक तंत्र को इस्लामिक ढंग से खास तौर पर शरिया के हिसाब से ढालना चाहते थे। यही कारण है उन्हें मिश्र में मुर्सीलीन (फासिस्ट मुसोलिनी की तर्ज पर) के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।

मोहम्मद मुर्सी मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेण्डे को शीघ्रता से लागू करना चाहते थे। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मिश्र पर कब्जे के दौरान साम्राज्यवाद के विश्वस्त औजार के रूप में हुयी थी। मुस्लिम ब्रदरहुड को मिश्र का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समझा जा सकता है। यह मिश्र के समाज का इस्लाम के आधार पर पुनर्गठन करना चाहता रहा है। नासिर ने इस संगठन पर पचास के दशक में प्रतिबंध लगा दिया था परन्तु इसका आधार व प्रभाव बना रहा है। 2011 में मुबारक के पतन के समय यह एक ऐसा संगठन था जो कि पूरी तरह से संगठित व देश व्यापी आधार लिए हुए था। धार्मिक गतिविधियों से लेकर यह संगठन आपदा के समय सामग्रियां बांटने जैसी हर तरह की कार्यवाहियों में सक्रिय था। इसे अरब की शेखशाहियों से भारी सहायता प्राप्त होती रही है और स्वयं मिश्र में भी पूंजीपतियों से लेकर छोटे दुकानदार तक इसको आर्थिक स्रोत मुहैय्या कराते रहे हैं।

मुबारक के खिलाफ उभरे जनाक्रोश में इसने हिस्सेदारी की और एक तरह से पहली दफा इसे व्यापक सामाजिक मान्यता मिली। मुबारक के पतन के बाद इसने अपने राजनैतिक विंग 'फ्रीडम एण्ड जस्टिस पार्टी' का गठन किया। मुर्सी मुस्लिम ब्रदरहुड का चुनावी चेहरा बन कर राष्ट्रपति चुनाव में उतरे। जून 2012 को मुर्सी एक ऐसे चुनाव में देश के राष्ट्रपति बने जो अपनी प्रक्रियाओं और समाज के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के विरुद्ध सेना द्वारा आयोजित करवाया गया था। उन्हें 51.7% मत प्राप्त हुए जबकि मुबारक काल में मंत्री रहे अहमद शफीक को 48.3 प्रतिशत मत मिले थे।

मुर्सी ने सत्ता सभालने के बाद तेजी से समाज के हर क्षेत्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेण्डा लागू करना शुरू कर दिया। चुनाव के समय किये गये वायदों व अन्य राजनैतिक पार्टियों व समूहों से किये गये समझौते को किनारे लगा दिया। मुबारक के समय की मिश्र की परम्परागत विदेश नीति से अलग उठाये गये कदमों खासतौर पर सीरिया और फिलिस्तीन के संदर्भ में उन्हें शक की निगाहों से देखा

जाने लगा। इजरायल व सीरिया के इस्लामिक विद्रोहियों के साथ उनकी बढ़ती निकटता को मिश्र में ठीक नहीं समझा गया। परन्तु जिस चीज ने उन्हें अधिक अलोकप्रिय बनाया वह नवम्बर 2012 में की गयी संवैधानिक घोषणा थी जिसके तहत मुर्सी ने अपने आपको सबसे बड़े संवैधानिक प्राधिकार के रूप में स्थापित कर दिया। मुर्सी के द्वारा लिए गये कार्यकारी निर्णयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मुर्सी ने पहले ही अपने मंत्रीमंडल में इस्लामिक कट्टरपंथियों को भरा हुआ था अब उन्होंने पूरे देश में कट्टर इस्लामिक पृष्ठभूमि वाले गवर्नरों की नियुक्ति शुरू कर दी। नवम्बर 2012 के सर्वसत्तावादी कदम से पूर्व मुर्सी ने मिश्र की संसद के ऊपरी सदन सूरा को ही वास्तविक संसद घोषित कर दिया। सूरा में इस्लामिक कट्टरपंथियों का वर्चस्व था जिनमें से अधिकांश को उन्होंने मनोनीत किया था।

सर्वोपरि बात यह थी कि मुर्सी के आर्थिक कदमों ने, जो कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण पाने के एवज में उठा रहे थे, मिश्र के आम नागरिकों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया। ईंधन, विद्युत से लेकर खाद्यान्न के दाम आसमान छूने लगे।

मुर्सी के मिश्र के समाज के इस्लामीकरण के कदमों से धार्मिक अल्पसंख्यकों खासतौर पर ईसाइयों के ऊपर हमले और अत्याचार बढ़ गये। मिश्र के समाज में जहां सूफी विचारों की बहुलता थी वहां शरिया के लागू करने के प्रयासों ने आम नागरिकों को चितिंत और परेशान कर डाला।

मुर्सी का विरोध वैसे तो उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरन्त बाद ही शुरू हो गया था परन्तु नवम्बर 2012 में उनके कदम के बाद विरोध बहुत तीव्र हो गया। मुर्सी के शासन काल में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब किसी न किसी कारण जनता सड़कों पर न रही हो। एक तथ्य के अनुसार वर्ष 2012 में 581 स्थानीय विरोध प्रदर्शन, 558 जुलूस प्रदर्शन, 514 मजदूर हड़तालें, 500 धरने आयोजित किये गये। (स्रोतः Egyptian Center For Social and Economic Rights)। ये आँकड़े मिश्र के समाज में मची उथल-पुथल की सिर्फ एक तस्वीर पेश करते हैं। वास्तव में समाज किस दिशा में जा रहा है इसका अंदाजा तब लगता है जब मुर्सी के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों का दौर वर्ष 2013 के अप्रैल-मई माह से शुरू होता है। मुर्सी के समर्थक और विरोधियों के बीच भयानक पैमाने पर झड़पें शुरू हो गईं।

अप्रैल 2013 में 'तामारोड' (विद्रोह) नाम से एक नया आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में उदारपंथियों से लेकर विभिन्न तरह के 'वाम' व गैर सरकारी संगठन शामिल थे। मुर्सी के इस्तीफे के लिए 'तामारोड' द्वारा चलाये गये हस्ताक्षर अभियान में उससे भी अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किये जितने लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में मुर्सी को मत दिया था। 'तामारोड' के अनुसार 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किये थे। 30 जून 2013 को लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर सड़कों पर उतर आये। तहरीर चौक पर पुनः वैसा ही नजारा उत्पन्न हो गया जैसा 28 जनवरी 2011 को होस्नी मुबारक के खिलाफ प्रदर्शनों के समय था। सेना इस बीच में मुर्सी के खिलाफ हो गयी थी। वह लगातार मुर्सी को चेतावनी दिये जा रही थी। अंततः 3 जुलाई 2013 को सेना ने मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से अपदस्थ कर दिया और मुर्सी के शासन काल के समय हुए अत्याचारों के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सेना ने वस्तुतः सत्ता अपने हाथ में ले ली परंतु 'तामारोड' की मांग के अनुसार सुप्रीम कॉन्स्ट्यूशनल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एडले मंसूर (Adley Mansour) को राष्ट्रपति बनाकर एक टेक्नोक्रैट सरकार गठित कर दी। सूरा सहित संसद को भंग कर दिया गया। आपातकाल लगा दिया गया। नये संविधान और शीघ्र ही चुनाव का वायदा किया गया। इस तथाकथित क्रांति के नायक के रूप में मिश्र की सेना के प्रमुख जरनल अब्देल फतेह अल-सिसी उभर कर आये। ऐसा कहा गया कि उनके हस्तक्षेप के कारण ही मुर्सी के इस्लामिक एजेण्डे के जाल से मिश्र मुक्त हुआ। वास्तव में सेना व जनता के अलावा शासक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मुर्सी के खिलाफ हो चुका था।

मुर्सी के समर्थन में मुस्लिम ब्रदरहुड सड़कों पर उतर आया। सेना और मुर्सी विरोधियों के बीच खूनी टकराहटों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मुस्लिम कट्टर- पंथियो ने ईसाइयों के ऊपर घातक हमले किये हैं। मिश्र के कोपटिक आर्थोडॉक्स पोप तवाड्रोस व अल-अजहर ग्रांड शेख अहमद अल-तैयब ने सेना के कदमों का स्वागत किया। कोपटिक पोप का सेना को समर्थन मुस्लिम ब्रदरहुड के ईसाइयों पर निशाने की एक वजह बना। सैन्य कार्यवाही में 15 अगस्त 2013 को काहिरा के नजदीक नासर सिटी स्थित राबा अल अडाविया मस्जिद में ब्रदरहुड के लगभग 2000 सदस्य मारे गये और हजारों घायल हो गये। यह संघर्ष अभी जारी है। मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी है।

सैन्य तानाशाही की पुनर्स्थापना

जुलाई 2013 में कायम हुई सैन्य तानाशाही ने वह रूप अख्तियार नहीं किया जो उससे पहले होता रहा था। इस बार उसने नागरिक सरकार का आवरण पहना हुआ है। सुप्रीम कॉन्स्ट्यूशनल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस सरकार के राष्ट्रपति हैं और इस सरकार को हाल-फिलहाल जनसमर्थन भी हासिल है। नवम्बर माह में आपातकाल को समाप्त कर दिया गया। आपातकाल समाप्त करने के पहले इस सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की। इस वक्त उसके सभी प्रमुख नेता जेल में हैं।

अमेरिकी साम्राज्यवादी सहित कई देशों ने कुछ आगे-पीछे विचार करने के बाद इसे सैन्य तख्तापलट के रूप में देखा है। अमेरिका ने मिश्र को प्रति वर्ष दी जाने वाली 1.5 अरब डालर की सैन्य सहायता पर रोक लगा दी। परन्तु अल-सिसी की सरकार की

सहायता के लिए आगे आयी अरब शेखशाहियों खास तौर पर सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात ने 16 अरब डालर के तुरन्त सहायता के पैकेज की घोषणा कर दी। यह पैकेज नकद राशि, तेल और निवेश से युक्त है। अल-सिसी ने रूस के साथ दशकों बाद सैन्य सम्बंध कायम कर लिये और रूस से भारी पैमाने पर हथियार की खरीददारी के समझौते किये।

अल-सिसी के वास्तविक नेतृत्व वाली सरकार को मुबारकवादियों, नासिरवादियों, विभिन्न वाम नामधारी पार्टियों, गैर सरकारी संगठनों का समर्थन हासिल है। इस्लामिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरह अल सिसी ने नासिर युग की यादें जनमानस में ताजा कर दीं।

फिलहाल अल-सिसी की सरकार शीघ्र ही एक नये संविधान और आम चुनाव का वायदा कर रही है। इस सिलसिले में कुछ कदम उसने उठा भी लिये हैं।

इस तरह से मिश्र ने इतिहास के एक चक्र को पूरा कर लिया है। मिश्र के लगभग पिछले तीन वर्षों का राजनैतिक घटनाक्रम यह साबित करता है मिश्र जिस उथल-पुथल के दौर से गुजरा है वह बीता नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड का जिस ढंग से सेना ने दमन किया उसे लेकर आम जनता में भारी क्षोभ मौजूद है हालांकि उसे मुर्सी व ब्रदरहुड की नीतियों और कार्यवाहियों के खिलाफ भी भारी रोष था जिसके कारण एक वर्ष में ही उसकी सरकार का पतन हो गया। फिलहाल मिश्र संक्रमण काल से गुजर रहा है।

III

मिश्र के जनविद्रोह का राजनैतिक अर्थशास्त्र

18 जून 1953 को मिश्र को एक गणतंत्र घोषित किये जाने से पहले मिश्र एक ऐसा देश था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संरक्षण में पूंजीवादी विकास तो प्रारम्भ हो चुका था परन्तु उसकी अर्थव्यवस्था में सामंतवाद का ही बाहुल्य था।' फ्री आफीसर्स मूवमेंट' के तहत शुरू हुए जनवादी आंदोलन जिसे मिश्र में 'पहली क्रांति' के नाम से आजकल सम्बोधित किया जाता है (दूसरी क्रांति से तात्पर्य 2011के होस्नी मुबारक के पतन से है। 25 जनवरी 2011 को आधिकारिक तौर पर क्रांति दिवस की मान्यता दे दी गयी है)। इस 'क्रांति' ने एक प्रक्रिया के तहत विऔपनिवेशीकरण, भूमि सुधार व वितरण, राष्ट्रीयकरण के कार्यभारों को अपने खास तरीके से सम्बोधित किया। 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के साथ गमाल अब्देल नासिर अरब राष्ट्रवाद के सशक्त प्रतिनिधि व नेता बनकर उभरे। यद्यपि मिश्र के गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति जरनल मुहम्मद नागिब थे परन्तु मिश्र की 'क्रांति' के असली सूत्रधार उनको हटाकर राष्ट्रपति बने नासिर ही थे।

अरब राष्ट्रवाद, जो कि उस समय अपने भीतर प्रगतिशीलता के तत्वों को समेटे हुए था, का ही जोर था कि सीरिया और मिश्र ने संयुक्त अरब गणतंत्र (यू.ए. आर.) का गठन 1958 में किया। यह गणतंत्र बहुत थोड़े ही समय 1961 तक अस्तित्व में रहा। 1961 में सीरिया इस गणतंत्र से अलग हो गया। मिश्र बहुत दिन यू.ए.आर. नाम को ढोता रहा परन्तु अनवर सादात के समय में उसने अपना नाम अरब रिपब्लिक ऑफ ईजिप्ट (ए.आर.ई.) कर लिया।

नासिर के अरब राष्ट्रवाद और अन्य नीतियों के पटाक्षेप की शुरूआत 1967 के अरब-इजरायल के छः दिवसीय युद्ध के साथ हो गई थी और उसके लगभग एक दशक बाद मिश्र में अनवर सादात ने नासिर की नीतियों और रास्ते को त्यागना शुरू कर दिया। नासिर 1967 में मिली हार के बाद अपना तेज खोने लगे और 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। नासिर के बाद राष्ट्रपति बने अनवर सादात ने 1975 तक नासिर के प्रयोगों को जारी रखा जिसमें वे नासिर से भी ज्यादा असफल रहे। 1973 में उन्होंने सीरिया के साथ मिलकर इजरायल पर यकायक आक्रमण किया परन्तु उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मिश्र को सिनाई हासिल तभी हो सका जब मिश्र ने इजरायल के साथ 1979 में विवादित कैम्प डेविड शांति समझौता किया। इस समझौते से खफा इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बाद में अनवर सादात की हत्या कर दी। 1981 में सादात की हत्या के बाद होस्नी मुबारक राष्ट्रपति बने।

अनवर सादात ने एक तरफ पश्चिमी साम्राज्यवादी पूंजी के मिश्र में प्रवेश को सुगम बनाने वाली नीति 'इनफिताह' [(infitah अरबी में, जिसका हिन्दी में अर्थ है 'खुला द्वार नीति' (open door policy)] को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ उन्होंने सोवियत संघ से अपने नजदीकी सम्बन्धों को समाप्त करके तेजी से अमेरिकी साम्राज्यवादियों से निकटता बढ़ायी। इसी निकटता के तहत उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवादियों के पश्चिम एशिया के निकट सहयोगी इजरायल व खाड़ी देशों की शेखशाहियों से भी सम्बन्धों को सुधारा। अनवर सादात के समय से सोवियत संघ से भंग सम्बन्धों को अब पुनः 2013 में अल-सिसी ने रूस से सैन्य सम्बन्धों की स्थापना कर पुनर्जीवित किया है। इसे ही कई लोग 'नासिरवाद' की वापसी के रूप में देख रहे हैं। नासिर के अरब राष्ट्रवाद की नींव सादात ने खोदनी शुरू की और मुबारक के काल में तो यह एक विस्मृत नारा बन गया।

अनवर सादात के समय ही मिश्र की अर्थव्यवस्था ऋण संकट की ओर अग्रसर होने लगी थी। होस्नी मुबारक के शासन में यह ऋण संकट गहराता गया। 1982-90 तक ऋण संकट के दबाव में मिश्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पेरिस क्लब के निर्देशों के अनुरूप ढांचागत समायोजन (Structural adjustment Program) के लिए बाध्य हुआ। इस प्रोग्राम के तहत मिश्र ने निजीकरण-उदारीकरण-वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाना शुरू किया। सामाजिक सेवाओं में कटौती, मूल्य निर्धारण नीति को सरल बनाना, खाद्य पदार्थों और तेल गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को घटाना, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना, आयात

प्रतिस्थापन की नीति को बदलकर, विदेशी पूंजी की आवाजाही को सुगम बनाना आदि से सम्बन्धित कदम इस नीति के तहत उठाये गये।

नासिर ने अपने राष्ट्रवादी रुझानों के तहत एक ऐसी केन्द्रीय अर्थव्यवस्था की नींव डाली थी जो सोवियत संघ के समाजवाद से प्रेरित थी। विऔपनिवेशीकरण, सामन्तवाद की नींव खोदने और तात्कालीन मिश्र के पूंजीपति वर्ग की जरूरतों और आकांक्षाओं को स्वर देने वाली नासिर की इस केन्द्रीयकृत अर्थव्यवस्था में आयात प्रतिस्थापन व राष्ट्रीयकरण की अहम भूमिका थी। परन्तु अस्सी का दशक आते-आते ये आर्थिक नीतियां मिश्र के पूंजीपति वर्ग की इच्छा व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रह गयी थीं। अनवर सादात ने बदलाव की जब शुरुआत की तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मुख्य खाद्य पदार्थों में सब्सिडी खत्म करने का नतीजा 1977 में दंगों के रूप में आया। इन दंगों को 'ब्रेड इन्तिफादा' के नाम से जाना जाता है। इन दंगों का अनवर सादात ने निर्ममतापूर्वक दमन किया जिसमें 160 लोग मारे गये और सैकड़ों घायल हो गये। परन्तु इस सबके बाद सादात को खाद्य सब्सिडी पुनर्बहाल करनी पड़ी। इन दंगों की पुनरावृत्ति 2008 में खाद्यान्न संकट के समय फिर से तब हुयी जब मुबारक ने भी सादात की तरह खाद्यान्नों पर सब्सिडी कम करने की कोशिश की। 2008 के इस खाद्यान्न संकट के समय खाद्य पदार्थों के दामों में तीस फीसदी से भी अधिक वृद्धि हो गयी थी। हालात यहां तक पहुंच गये कि मजदूर वर्ग के वेतन का आधे से अधिक हिस्सा भोजन पर ही खर्च होने लगा।

होस्नी मुबारक ने उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण की नीतियों को नब्बे के दशक में तेजी से आगे बढ़ाया। इन नीतियों के कारण जहां पूंजीपति वर्ग की दौलत में तेजी से वृद्धि हुई वहीं शेष आबादी के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें बरसने लगी। मिश्र के राज्य की सम्पत्तियां तेजी से मिश्र के पूंजीवादी एकाधिकारी घरानों को सौपी जाने लगी। एक तथ्य के अनुसार मुबारक के कार्यकाल में सिर्फ 1981 से 2006 के बीच में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पी.पी.पी. की दर से) तीन गुने से अधिक हो गया था। यह तालिका विभिन्न आधारों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को दिखाती है। कृपया तालिका-1 देखें।

तालिका से स्पष्ट है कि होस्नी मुबारक काल में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 1981 से 2006 के बीच विभिन्न आधारों पर कई गुना की वृद्धि को चुकी थी। यह वृद्धि आम मजदूरों व नागरिकों की आय व सम्पत्ति में नहीं हो रही थी वहां स्थिति उलट थी।

सच तो यह है कि मिश्र के उत्पादन और सम्पत्ति में मुबारक के समय में वृद्धि हो रही थी परन्तु इसी समय न्यूनतम मजदूरी मुद्रास्फीति के लगातार बढ़ने के बावजूद 26 सालों तक अपरिवर्तित रही। मिश्र का पूंजीपति वर्ग और राज्य मजदूरों को बुरी तरह से निचोड़ रहा था। उसके काम के घण्टों में लगातार वृद्धि हो रही थी। विश्व श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के अनुसार मिश्र दुनिया के उन पच्चीस देशों में था जहां श्रम कानूनों की स्थिति सबसे बुरी थी। इसमें और बुरी बात यह थी कि मजदूरों का एकमात्र संगठन इजिप्सीयन ट्रेड यूनियन फेडरेशन (ETUF) में होस्नी मुबारक के समर्थकों का बोलबाला था और वह मुबारक की नव-उदावादी नीतियों का खुला समर्थन कर रहा था। मुबारक के कार्यकाल के शुरुआती दशकों में ही खाद्य सब्सिडी पचास फीसदी तक कम कर दी गयी थी। (तथ्य स्रोत: http//monthly review.org/2011/11/01/the-political-economy-of-the egptian-uprising)

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि न होना, खाद्य पदार्थों के दामों में हो रही तेज वृद्धि, काम के घण्टों में वृद्धि व श्रम कानूनों के लागू न होने आदि कारणों से 2004 से 2010 के समय में श्रमिक हड़तालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। श्रमिक असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। जिसके सबसे बड़े लाक्षणिक उदाहरण के रूप में माहल्ला टैक्सटाइल मजदूरों का 2006 का छः अप्रैल का आंदोलन (6th April movement) था। जिसके नाम पर 2008 में एक गैर सरकारी संगठन "सिक्स्थ अप्रील मूवमेंट" के नाम से पैदा हो गया था। मजदूर वर्ग के साथ-साथ समाज के अन्य शोषित-उत्पीड़ित तबकों में असंतोष फैल रहा था। खासकर युवा बेरोजगारी व अनिश्चित भविष्य को लेकर व्यग्र थे।

सितम्बर, 2009 में जहां विश्व बैंक मिश्र को चौथी बार दुनिया के उन दस देशों की श्रेणी में रख रहा था जहां सबसे तत्परता के साथ आर्थिक सुधार लागू किये गये थे। वहां समाज में खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों के साथ उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी दर और न्यूनतम वेतन के कारण मजदूरों, युवाओं, निम्न मध्यम वर्ग के साथ छोटे किसानों में अपनी बदहाली को लेकर रोष फैल रहा था।

होस्नी मुबारक के शासन में पुलिस और सेना के अत्याचार और सामान्य नागरिक अधिकारों का अभाव तेजी से समाज को 2011 के जनविद्रोह की ओर धकेल रहे थे। इस विषय पर और चर्चा करने के पहले मिश्र की अर्थव्यवस्था का एक जायजा ले लें।

मिश्र की अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर

सेना नियंत्रित सरकार के गठन के बाद 2013 में मिश्र की 'स्टेट इन्फॉर्मेशन सर्विस' मिश्र की अर्थव्यवस्था की समस्याओं और समाधान के संदर्भ में कहती है :

"मिश्री अर्थव्यवस्था : समस्यायें और समाधान

अर्थव्यवस्था खतरे में है। सुप्रीम काउन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा हाल में एक सेमिनार "जनवरी क्रांति और आर्थिक वृद्धि के क्षितिज (January Revolution and Horizons of Economic Growth)" शीर्षक से आयोजित हुआ था। जिसमें मिश्र की अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व आर्थिक गिरावट की स्थिति की अन्तिम रूप से व्याख्या करने वाली एक टिप्पणी स्थिति को इस तरह से बयां करती है।

सूचकांक दिखलाते हैं :

- गरीबी की दर 70% है;
- आर्थिक वृद्धि 1 से 2% के बीच गिर चुकी है;
- विदेशी मुद्रा भण्डार (hard currency reserves) 36 अरब से 28 अरब डालर हो चुका है;
- विदेशी निवेश प्रवाह शून्य तक पहुंच चुका है;
- बजट घाटा 1290 अरब डालर ई.जी.पी.तक पहुंच गया है;
- सामान्य घाटे की गणना 1080 अरब ई.जी.पी. है जो जी.डी.पी का 90% है;
- पर्यटन से होने वाली आय 40% तक गिर गयी है;
- स्टॉक एक्सचेंज को 20 ई.जी.पी. का नुकसान हो चुका है;

सेमिनार ने कई समाधान पेश किये जो ये हैं :

- ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें निवेश और पर्यटक आकर्षित हो सकें;
- ऐसी आर्थिक स्थिति तैयार करना जिससे कि मुद्रा बाजार (Money market) को दुबारा से शुरू करना सुनिश्चित किया जा सके;
- बैंकिंग तंत्र को विकसित करना और निवेश पारदर्शिता को संस्थागत करना;
- भ्रष्टाचार से लड़ना और लोकतंत्र को सुदृढ़ (consolidate) करना;
- देश के वित्तीय और मौद्रिक क्षेत्रों को सुरक्षित करना। " ... ... (State information Service, Egyptian Economy : Problems and Solutions, 31 oct 2013)

यह वक्तव्य अपने आप में मिश्र की अर्थव्यवस्था की आज की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कह देता है। मिश्र की अर्थव्यवस्था की समस्याओं और समाधान के बारे में मिश्र के शासक वर्ग के दृष्टिकोण को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कर देता है। समस्याओं के प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले गरीबी गिनायी गयी जबकि समाधान में ऐसा वातावरण तैयार करना कि निवेश हो सके, और पर्यटक आ सकें। इस सेमिनार में वर्तमान सरकार के कई मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री सहित कई अन्य 'गणमान्य' व्यक्तियों ने भागीदारी की थी।

पिछले तीन-चार दशकों में मिश्र की अर्थव्यवस्था की संरचना भी पूंजीवादी दुनिया की अन्य आम अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप ही होती चली गयी है। जिसका एक खास लक्षण अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के हिस्से का सबसे बड़ा व निर्णायक होना है। मिश्र में सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के आधे के बराबर है। वर्ष 2012 के एक अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 14.7%, उद्योग 37.04% तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा 47.9% था। मिश्र के वर्तमान फौजी शासकों ने मिश्र की अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्यायें गिनायीं व समाधान से सम्बन्धित जितनी बातें गिनायीं वे सेवा क्षेत्र से ही सम्बन्धित हैं। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बड़े हिस्से की तरह ही श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में ही लगा हुआ है। 2001 के एक अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में 51 फीसदी, कृषि में 32 फीसदी व उद्योग में 17 फीसदी श्रम शक्ति लगी हुई है। इस तरह से मिश्र की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा हिस्सा हैं और उसी में श्रम शक्ति की बड़ी आबादी लगी हुई है।

मिश्र में बेरोजगारी की समस्या वर्तमान जनविद्रोह के कई वर्ष पहले से ही विकराल होती जा रही थी। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार ही बेरोजगारी दस वर्षों से दस प्रतिशत के आसपास रही है। वर्तमान संकट के प्रारम्भ में युवाओं में बेरोजगारी 25 फीसदी तक जा पहुंची। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिश्र के 60 प्रतिशत नागरिक तीस वर्ष से कम आयु के हैं। मिश्र की अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर तालिका-2 से उभरती है।

तालिका-2 मिश्र की अर्थव्यवस्था के 2001 से 2008 तक के समय की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे होस्नी मुबारक की निजीकरण-उदारीकरण- वैश्वीकरण की नीतियों को समझा जा सकता है। साथ ही इन नीतियों के कारण उत्पन्न होने वाले संकट का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे एक तरफ मिश्र के सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर में 2001 से 2008 के बीच में लगातार वृद्धि हुई और दूसरी तरफ इस दौरान मुद्रास्फीति भी लगातार बढ़ती चली गयी और 2004 में दस फीसदी से ऊपर पहुंच गयी। ऐसे ही एक तरफ मिश्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2001 से 2006 के दौरान भारी वृद्धि हुई परन्तु इसके साथ-साथ मिश्र की मुद्रा डालर के मुकाबले गिरती चली गयी।

तालिका-3 व तालिका-4 मिश्र की अर्थव्यवस्था सरकार के आय-व्यय व उस पर बढ़ते ऋण को दिखलाती हैं। ये तालिकायें बता रही हैं कि मिश्र का समाज इस सदी के पहले दशक में उस दिशा में बढ़ रहा था जहां होस्नी मुबारक की नीतियां दूसरे दशक के सामाजिक उथल-पुथल की भौतिक जमीन को शनैःशनैः तैयार कर रही थीं।

तालिका-4

मिश्र सरकार के घरेलू ऋण (2001-2007)

तालिका-3 दिखला रही है कि सरकार का कुल घाटा तेजी से बढ़ता जा रहा था। और यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद के इस दौरान करीब 7 फीसदी और कई वर्षों में उससे भी ऊपर रहा है। इस घाटे को पाटने के लिए सरकार अपने विभिन्न बॉण्डों को जारी करके घरेलू बाजार से में जुटा रही थी। यह ऋण 2007 में सकल घरेलू उत्पाद के 65% तक जा पहुंचा था।

तालिका-3 विभिन्न वर्षों में निजीकरण से होने वाली प्राप्तियों को भी दर्शा रही है। लेकिन इससे ठीक तस्वीर नहीं उभर पाती है। भारत के अनुभव से हम जानते हैं कि नई आर्थिक नीति के दौर में सरकार ने किस तरह से राष्ट्रीय सम्पत्तियों व संसाधनों को निजीकरण की नीति के तहत देशी-विदेशी पूंजी को औने-पौने दामों में बेच डाला। भारत में हाल के समय के 2-जी स्पेक्ट्रम व कोयला घोटाला इसकी एक तस्वीर पेश करते हैं। वास्तव में मिश्र में निजीकरण की प्रक्रिया तेज रही है। ग्लोबल रिसर्च के एक लेख के अनुसार "1991 से 2009 के बीच में मुबारक प्रशासन ने राज्य की 382 कम्पनियों को निजी निवेशकों को 9.4 अरब डालर में बेच डाला।" ('Legacy of the''Arab Spring, Egypt for Sale ,The Bitter Taste of IMF'' Economic Medicine,' www. global research)

राज्य की सम्पत्ति को निजी हाथों में सौंपने का एक नतीजा यह निकला कि मिश्र में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई। कई एकाधिकारी घराने तो इतने बड़े हो चुके हैं कि वे फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। ये एकाधिकारी घराने मिश्र की राजसत्ता से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और उसकी नीतियों व दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तालिका-5 में ऐसी तीन कम्पनियों के बारे में बताया गया है जो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में शामिल हैं। मिश्र में ऐसी विशाल एकाधिकारी कम्पनियों का पैदा हो जाना होस्नी मुबारक की नवउदारवादी नीतियों का ही परिणाम है।

तालिका-5

स्रोत : विकीपीडिया

इन एकाधिकारी कम्पनियों के होस्नी मुबारक की सरकार, उनकी पार्टी और उनके परिवार से घनिष्ठ सम्बंध रहे हैं। इन कम्पनियों के मालिक सरकार और पार्टी में भागीदारी करते रहे हैं। मुर्सी के खिलाफ हुए जनविद्रोह के एक प्रमुख संगठन 'तामारोड' को इन कम्पनियों ने भारी मात्रा में धन मुहैय्या करवाया। यही बात एक हद तक मुर्सी पर लागू होती है कि उनकी सरकार व मुस्लिम ब्रदरहुड को व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकारी स्थिति रखने वाली कम्पनियों, अन्य व्यापारिक छोटे-बड़े समूहों के साथ शेखशाहियों से पैसा मिलता रहा है।

मिश्र की अर्थव्यवस्था में आज कृषि का हिस्सा महज 15 फीसदी तक रह गया है। मिश्र की अर्थव्यवस्था में पिछली सदी के पांचवें व छठे दशक तक कृषि का हिस्सा अहम् था। परन्तु 1960 आते-आते इसका सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा गिरकर 28 प्रतिशत तक जा पहुंचा जो कि 1998 में और गिरकर महज 17.5 फीसदी रह गया। इसके अनुरूप ही कृषि में कार्यरत आबादी जहां 1960 में आधे से अधिक करीब 54 फीसदी थी वह 1997 में घटकर महज 30.8 फीसदी रह गयी। (तालिका-6 देखें)

मिश्र में कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी समाज की चुनौतियों के साथ-साथ प्राकृतिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मिश्र का 96 फीसदी हिस्सा रेगिस्तान है। मिश्र के कुल क्षेत्रफल में केवल 3 फीसदी क्षेत्र ही कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। मिश्र के कृषि क्षेत्र का 90 फीसदी हिस्सा नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में है और शेष नील नदी के साथ-साथ के उस हिस्से में है जो आसवान बांध और काहिरा के बीच है तथा एक पट्टी भूमध्य सागर के साथ-साथ है।

मिश्र के कृषि क्षेत्र को बढ़ते रेगिस्तानी क्षेत्र ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आसवान बांध के निर्माण और उससे निकाली गयी नहरों और अन्य तरीकों से रेगिस्तान से एक समय, खासकर नासिर के समय में कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया गया परन्तु बाद में हर पूंजीवादी देश की तरह मिश्र में भी कृषि अपने दोयम दर्जे व उपेक्षा के कारण गम्भीर संकट का शिकार होने लगी। तालिका-7 जो इस सदी के गेहूँ और मक्के के उत्पादन को दर्शा रही हैं, को देखने पर पता चलता है कि इन दो प्रमुख उपजों का उत्पादन लगभग स्थिर सा है जबकि उपभोग लगातार बढ़ता चला गया है। बढ़ते रेगिस्तान के साथ मिश्र के बढ़ते शहरीकरण ने भी खेती योग्य जमीन, जो पहले ही काफी कम है, के सामने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है।

एक समय मिश्र के निर्यात में कृषि उत्पादों (जिसमें पशु और मांस वगैरह भी शामिल हैं) का एक बड़ा हिस्सा होता था। 1960 में कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 87 फीसदी था। 1974 में यह गिरकर 35 फीसदी और 2001 में मात्र 11 फीसदी रह गया था।

मिश्र अपनी खाद्य जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। इसमें वह मूलतः अमेरिका पर निर्भर रहा है। गेहूँ व मक्के के आयात के लिए मिश्र अमेरिका के अलावा कजाकिस्तान, अर्जेन्टीना, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, सीरिया व रूस पर निर्भर रहा है। खाद्य पदार्थों पर मिश्र की निर्भरता उसे वैश्विक खाद्यान्न बाजार में होने वाली उठापटक के कारण बहुत अधिक प्रभावित करती रही है। तालिका-7 से स्पष्ट है कि मिश्र में गेहूँ और मक्का के उपभोग में अमेरिका से आयात की बड़ी हिस्सेदारी रही है।

तालिका-6

(स्रोतः FAO STAT)

मिश्र के मुख्य कृषि उत्पाद सूत, गेहूँ, चावल, मक्का, बीन्स, सब्जियां आदि हैं। कपास उत्पादन मिश्र के टैक्सटाइल उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिश्र के निर्यात में क्रूड ऑयल, पेट्रो उत्पाद, सूत, टैक्सटाइल धातुएं, रसायन और निर्मित खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं।

तालिका-7

गेहूँ और मक्के का मिश्र में उत्पादन, आयात और कुल उपभोग

(वित्तीय वर्ष और हजार मीट्रिक टन में)

स्रोत : विकीपीडिया 2013

मिश्र के आयात में मशीनरी व उपकरण, खाद्य पदार्थ, रसायन, तेल और काष्ठ पदार्थ प्रमुख हैं। तालिका-8 मिश्र के आयात-निर्यात में प्रमुख स्थान रखने वाले देशों की सूची दिखलाती है।

तालिका-8

मिश्र का आयात-निर्यात (वर्ष 2012)

(स्रोतः सी.आई.ए. फैक्ट फाइल)

मिश्र की अर्थव्यवस्था अरबजगत में सऊदी अरब के बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्टील उत्पादन, ऑटो मोबाइल क्षेत्र, निर्माण उद्योग में मिश्र अफ्रीका व अरब देशों में शीर्ष स्थान रखता है। स्टील के मामले में मिश्र का स्टील उद्योग अफ्रीका व अरब में सबसे बड़ा है। ई.जेड.डी.के. इस क्षेत्र में स्टील का निर्माण करने वाली बहुत बड़ी एकाधिकारी कम्पनी है। टैक्सटाइल व वस्त्र निर्माण में भी मिश्र का स्थान अग्रणी है। यूरोप के करीब होने के चलते यहां वस्त्र निर्माण क्षेत्र को जहां इसका लाभ मिलता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि मिश्र, जहां पर सेना के नेतृत्व में फौजी शासकों का एकछत्र शासन रहा हो, में उन्हें सस्ते मजदूर आसानी से उपलब्ध होते रहे हैं। एक तथ्य के अनुसार,"मिश्र के गैर-तेल उत्पादों के निर्यात में टैक्सटाइल उद्योग का हिस्सा एक चौथाई है ...। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां सूत कताई में 90 फीसदी, कपड़ा निर्माण में 60 फीसदी, और वस्त्र निर्माण में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखती हैं। 'मिस्र फाइन स्पीनिंग एण्ड वीविंग' अफ्रीका और मध्य पूर्व में इस तरह की सबसे बड़े उपक्रमों में विशालतम है। मिश्र में निजी क्षेत्र वस्त्र निर्माण में सबसे अधिक सक्रिय है" (विकीपीडिया)। इस क्षेत्र के मजदूरों की हालिया जनविद्रोह में सक्रिय व प्रभावशाली भूमिका रही है।

हाल के दशकों में मिश्र में तेल व प्राकृतिक गैस के भण्डार भी मिले हैं। पश्चिमी एशिया के देशों को प्राकृतिक गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्त्ताओं में मिश्र शामिल है। हाल के वर्षों में मिश्र के डेल्टा क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर तेल और खासकर प्राकृतिक गैस के नये भण्डार मिले हैं। 2009 में अनुमान लगाया गया कि मिश्र में क्रूड ऑयल का 3.7 अरब बैरल और प्राकृतिक गैस का 6.56 खरब घन मीटर भण्डार है। गाजापट्टी की ईंधन की जरूरतें मिश्र के द्वारा ही पूरी की जाती रही हैं। मुर्सी के शासन काल में इजरायल से सम्बंध सुधारने के नाम पर इस आपूर्ति में बाधा पहुंची मिश्र जॉर्डन, इजरायल व सीरिया को प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) को प्रमुख रूप से निर्यात करता रहा है। सीरिया के प्राकृतिक गैस की कुल खपत का 20 फीसदी मिश्र द्वारा निर्यात किया जाता रहा है।

मिश्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से होने वाली आय का भी अहम् हिस्सा है। यह रोजगार और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत रहा है। विकीपीडिया में उपलब्ध तथ्य के अनुसार वर्ष 2009-10 में पूरी दुनिया के कुल पर्यटन उद्योग का 1 फीसदी हिस्सा मिश्र का था। 2011-13 की घटनाओं ने पर्यटन उद्योग को खासा प्रभावित किया है। मिश्र के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का हिस्सा करीब 6 फीसदी रहा है।

पर्यटन के अलावा मिश्र की विदेशी मुद्रा का अन्य प्रमुख स्रोत प्रवासी मिश्री कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली आय है। विकीपीडिया के ही तथ्यों के अनुसार वर्ष 2009 में इसका मिश्र के सकल घरेलू उत्पाद में 5 फीसदी हिस्सा था। संयुक्त राज्य अमेरिका (23%), कुवैत (15%), संयुक्त अरब अमीरात (14%) और सऊदी अरब (9%) प्रमुख उन देशों में थे जहां से मिश्री कामगार अपने देश को धन भेजते थे। विश्व आर्थिक संकट और वर्ष 2011 से अरब देशों में जारी सामाजिक उथल- पुथल का असर मिश्र की इस आय पर भी पड़ा है।

अर्थव्यवस्था में मिश्र की सेना की भूमिका :

पाकिस्तान की तरह मिश्र की अर्थव्यवस्था में मिश्र की सेना का अत्यधिक हस्तक्षेप है। हाल के एक अनुमान के अनुसार वह अर्थव्यवस्था के 40 फीसदी तक को नियंत्रित करती है। (स्रोतः फ्रंटलाइन, सितम्बर 2013) आमतौर पर यह माना जाता है कि सेना की मिश्र की अर्थव्यवस्था में 25 फीसदी की हिस्सेदारी है।

मिश्र की सेना का दखल अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्रों-कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र-में है। वह हथियार बनाने के उद्योग से लेकर उपभोक्ता सामग्रियों तक का उत्पादन करती है। वह बड़े-बड़े कृषि फार्म संचालित करती है। अस्पताल, क्लब, गैस स्टेशन, सड़क, इमारत, पुल इत्यादि के निर्माण के ठेके व संचालन का काम करती है। रियल स्टेट के कारोबार में भी वह सक्रिय है। इस तरह से देखा जाय तो मिश्र की सेना अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सक्रिय है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में सेना के उच्च अधिकारियों की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाती है। निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों का फायदा सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी खूब मिला है। सेना में इस कारण से भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद का अच्छा खासा बोलबाला है। मिश्र के पूंजीपति वर्ग में सेना के वर्तमान और सेवानिवृत अफसरों का एक ठीक-ठाक हिस्सा बन जाता है। मुर्सी के तख्तापलट में सेना के इस वर्ग के साथ नौकरशाह पूंजीपति वर्ग ने अपने हितों के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। मुर्सी मिश्र की बिगड़ती आर्थिक स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नये ऋण ले रहे थे जिसमें सरकारी खर्चों

में तेजी से कटौती के साथ निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों को लागू करना था। मुर्सी की नीतियां सेना के हितों के खिलाफ भी जा रही थी। जन दबाव के साथ यह भी कारण है कि अल सिसी की सरकार ने इस ऋण व शर्तों को नकार दिया।

मिश्र में सेना के कारोबार की सभी सूचनाएं गुप्त सूचनाओं के दायरे में आती हैं इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था में सटीक भूमिका का आकलन सम्भव नहीं हो पाता है। यह उसे अनेकों विशेष अधिकार प्रदान करता है। सेना के द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों में काम करने वाले मजदूरों और अन्य कर्मचारियों की स्थिति बेहद कठिन व जटिल है। सेना देश सेवा के नाम पर उनका बुरी तरह शोषण व उत्पीड़न करती है। उनकी कार्य परिस्थितियां अत्यंत बुरी हैं और उनके संगठित होने में सेना हजारों अड़चनें डालती है।

भूमि के मामले में भी मिश्र की सेना के पास विशेषाधिकार हैं। उसकी स्थिति ऐसी है कि एक तरह से मिश्र की जमीन का अधिकांश हिस्सा उसके पास ही है। मिश्र में केवल आठ फीसदी जमीन ही पंजीकृत (registered) है। सेना के पास गैर पंजीकृत जमीन का इस्तेमाल करने का अघोषित अधिकार है। यह जमीन सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस विशाल जमीन का इस्तेमाल सेना और सरकार से जुड़े अधिकारी मनमाने ढंग से करते हैं। इस जमीन पर होने वाली आर्थिक गतिविधियां किसी सरकारी दस्तावेज का हिस्सा नहीं बनती हैं।

मिश्र की अर्थव्यवस्था के इस संक्षिप्त विवरण के बाद पुनः 2011-13 की हालत पर चर्चा करें।

जनविद्रोह के दौरान आर्थिक हालात :

मिश्र के 'स्टेट इन्फॉर्मेशन सर्विस' का एक वक्तव्य कहता है:

"25 जनवरी की क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था :

"क्रांति और राजनैतिक संक्रमण के बाद राज्य ने हमेशा उत्पादन क्षेत्र की प्रगति में एक गम्भीर त्रुटि (Flaw) का सामना किया है जिसने पूरे देश की आर्थिक प्रगति पर असर डाला है। आजकल मिश्र इस अवस्था से गुजर रहा है।

"25 जनवरी 2011 की क्रांति के बाद जिन कारकों ने आर्थिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है उनकी समीक्षा इस प्रकार है:

"क्रांति के बाद के महीनों में गिरती सुरक्षा स्थिति ने कई क्षेत्रों में उत्पादन को स्थगित करने की ओर बढ़ाया जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय आय में गिरावट आयी।

"सीमाओं पर गैरकानूनी हथियारों के प्रवाह और विध्वंसक तत्वों की घुसपैठ के कारण सैन्य बलों ने बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना किया। ये तत्व अपनी उग्र कार्यसूची (agenda) थोपने की कोशिश कर रहे थे जिसका विपरीत प्रभाव पर्यटकों के प्रवाह और निवेश की दरों पर पड़ा।

"बढ़ते हुए धरने और कर्मचारियों के दावे।

"संक्रमण काल प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों से भरा हुआ था और पहले चुने हुए राष्ट्रपति के शुरुआती महीनों में अशांति थी।

"इन कारणों का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मिश्र की क्रेडिट रेटिंग की गिरावट और घरेलू तथा विदेशी ऋणों की ब्याज दरों की बढ़ोत्तरी के रूप में निकला। इससे आगे निवेश के अवसर कम हो गये, पर्यटकों के आर्कषक स्थलों ने अपने ग्राहक खो दिये और नकद आरक्षित निधि में कमी आ गयी।

"अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से एक ऋण समझौते को केन्द्रीय समाधान के रूप में लिया गया जिसे मिश्र की अर्थव्यवस्था की योग्यता के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र के रूप में देखा गया।" (Economy after January 25 th Revolution,' State Information Service Internet, अनुवाद हमारा)

मुर्सी काल का यह सरकारी वक्तव्य बतलाता है कि मिश्र की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के समाधान का एकमात्र रास्ता अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण ही है। मुर्सी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 4.8 अरब डालर ऋण लिया जिसके एवज में मुर्सी को मुद्रा कोष की कई शर्तें माननी पड़ी। जिसके तहत सब्सिडी को कम करना था। इसका प्रभाव सीधे तौर पर खाद्यान्न, गैस, बिजली आदि चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ करों में वृद्धि के रूप में पड़ा। मिश्र की सेना ने मुर्सी के सत्ता संभालने के पहले और बाद में जब उन्हें सत्ता से हटा दिया गया, दोनों ही अवसरों पर मुद्रा कोष के ऋण की शर्तों से इंकार कर दिया। सेना ने मुर्सी के सत्ता से हटने के बाद मुर्सी काल में लिये गये ऋण को लेने से इंकार कर दिया। ये शर्तें मिश्र के जनाक्रोश को और अधिक भड़काने वाली थीं।

असल में मुर्सी की नीतियों ने उन्हें नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के साथ सरकारी कर्मचारियों के बीच भी अलोकप्रिय बना दिया था। साम्राज्यवादी संस्थाओं के दबाव में मुर्सी राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के तेजी से निजीकरण की वकालत कर रहे थे और ऐसे ही कदम उठा रहे थे। करीब 68 लाख सरकारी कर्मचारियों के हित मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार से टकरा रहे थे। ये नीतियां सेना के भी हितों को नुकसान पहुंचा रही थीं। जैसे कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि मिश्र की सेना अर्थव्यवस्था के लगभग एक चौथाई हिस्से को नियन्त्रित करती है। इसी तरह कुल सरकारी नौकरियों में एक तिहाई सेना के पास हैं। सेना ने इसी वजह से ऐसे ऋण को वरीयता दी जो उसे ऐसी नीतियों पर जोर देने के लिए बाध्य न करे जिससे आम जनता का आक्रोश और बढ़े और प्रत्यक्षतः उसके हितों को भी नुकसान पहुंचे।

मुर्सी को सत्ता से हटाने के बाद सेना ने मुर्सी के समय उठाये गये अलोकप्रिय आर्थिक कदमों से अपने हाथ खींच लिये। मुद्रा कोष के बजाय उसने अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक करने के नाम पर पड़ोसी और अरब देशों से विदेशी सहायता हासिल की। कतर ने 8 अरब, तुर्की और लीबिया ने 2-2 अरब डालर दिये। इस सहायता ने सेना द्वारा नियन्त्रित सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से मोल-तोल करने में अधिक सक्षम और अधिक समय उपलब्ध करा दिया। फिलवक्त सेना आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिशों में लगी है। इसके लिए वह वायदों, दावों के साथ धूर्ततापूर्ण ढंग से रचे गये संवैधानिक प्रावधानों का भी सहारा ले रही है।

मिश्र में मुर्सी के शासन के खिलाफ उमड़े जनविक्षोभ में मुबारक के शासन काल की तरह महंगाई की भी अहम भूमिका थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के एक अनुमान के अनुसार दिसम्बर, 2012 से अगस्त, 2013 के आठ महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर दुगुनी हो गई और यह 10 फीसदी तक जा पहुंची। मिश्र की मुद्रा का अवमूल्यन, विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में कमी, विदेशों से मिश्र के कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली आय में कमी आदि के साथ मुर्सी की अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों के अनुरूप सब्सिडी में कटौती और टैक्सों में वृद्धि ने मिश्र के आम नागरिकों के जीवन को मुबारक काल से भी ज्यादा कठिनाई में डाल दिया। बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरी अप्रत्यक्षतः गिरती ही चली जा रही थी। सरकारी कर्मचारियों के बीच भी असंतोष महंगाई और बढ़ते निजीकरण के खतरे के कारण बढ़ता ही जा रहा था। इसी दौरान ईंधन के दामों में भी वृद्धि लगातार होती रही। इससे भी बढ़कर वे बाजार में अपने कानूनी दाम के मुकाबले 40 से 80 फीसदी अधिक दामों में बिक रहे थे। पहले मुबारक और बाद में मुर्सी महंगाई की समस्या पर किसी भी तरह काबू पाने में असमर्थ रहे। और आज सेना नियंत्रित सरकार के सामने भी यह समस्या मुँह बाये खड़ी है।

मुर्सी के बाद शासन संभालने पर सेना द्वारा नियंत्रित सरकार ने जहां एक तरफ मजदूरों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया वहीं दूसरी ओर उन्होंने मजदूर संघर्षों के दबाव के कारण न्यूनतम मजदूरी में छः गुने की वृद्धि भी की। सेना साम-दाम-दण्ड-भेद हर तरह की नीति अपनाकर मजदूरों व कर्मचारियों के संघर्षों को कुंद करना चाहती है।

मुबारक के पतन के बाद विदेशी मुद्रा भण्डार में भी तेजी से कमी आयी। पहले मुर्सी और अब सेना द्वारा नियंत्रित सरकार के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। यह अर्थव्यवस्था के हालात के बारे में पहले उद्धृत किये गये सरकारी वक्तव्यों से भी सुस्पष्ट है। एक तथ्य के अनुसार मुबारक के पतन के बाद विदेशी मुद्रा भण्डार में बहुत तेजी से कमी आयी। दिसम्बर, 2010 में विदेशी मुद्रा भण्डार 36 अरब डालर था जो कि जनवरी, 2012 में गिरकर मात्र 16.3 अरब डालर रह गया था। (स्रोतः विकीपीडिया,सी.आई.ए. फैक्ट फाइल इत्यादि।)

मिश्र के शासक वर्ग के लिए साम्राज्यवादी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली रेटिंग भी एक समस्या बनी हुई है। फरवरी, 2012 में 'स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स' नामक संस्था ने मिश्र की क्रेडिट रेटिंग (लांगटर्म) B+ से घटाकर B - कर दी और यही रेटिंग 2013 में घटाकर CCC+ कर दी। मिश्र की गिरती रेटिंग ने उसे विदेशी पूंजी के प्रवाह और निवेश के लिए और भी अनाकर्षक जगह बना दिया। कदाचित मुर्सी और उसके बाद सैन्य नियंत्रित सरकार ने इसीलिए इसे अपने प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाये जिससे निवेश और पर्यटक आकर्षित हो सकें। मुर्सी अपने शासन काल के दौरान न तो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और न ही देशी-विदेशी पूंजी की।

मुबारक काल के बाद मुर्सी को अमेरिकी साम्राज्यवादी ही नहीं बल्कि पश्चिम के अधिकांश साम्राज्यवादी हर तरह से समर्थन दे रहे थे। तुर्की इजरायल, सऊदी अरब जैसे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के अति निकट सहयोगी भी मुर्सी का समर्थन कर रहे थे। मुर्सी उनके विश्वासपात्र थे परन्तु वह जनविद्रोह की ऊर्जा से ओतप्रोत मिश्र के मजदूरों-मेहनतकशों के साथ मिश्र के एकाधिकारी घरानों के बड़े हिस्से के साथ सेना सहित नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की इच्छा व आवश्यकता के अनुरूप मिश्र की अर्थव्यवस्था की सेहत को ठीक नहीं कर सके। कोढ़ में खाज यह कि वे तेजी से अपने संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेण्डा लागू करने लगे। और तब तो उन्होंने अपने ताबूत में अपने आप कील ठोंक दी जब राष्ट्रपति को पूरी व्यवस्था के ऊपर घोषित कर दिया। और फिर मुर्सी के खिलाफ उमड़े जनाक्रोश का लाभ उठाकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन सेना ने मिश्र के हालिया घटनाक्रम से यह सबक लिया था कि उसके द्वारा सीधे सत्ता हाथ में लेने पर जनाक्रोश तुरन्त उसके खिलाफ भी फूट पड़ेगा। सेना ने एक ऐसी नागरिक सरकार का गठन किया जिसमें ऐसे लोगों की भरमार है जो मुबारक के समय सत्ता प्रतिष्ठानों में काबिज थे। वस्तुतः सेना के हाथ में ही सत्ता है। जनरल सिसी कहने को इस सरकार में रक्षामंत्री हैं परन्तु वे प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं। वे सत्ता के केन्द्र हैं। वे सेना की ताकत व आधार के साथ उस नैतिक प्राधिकार (Moral authority) का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी भी मिश्र की सेना की मिश्र के समाज में बनी हुई है। मुर्सी के पास एक संगठित राजनीतिक समूह ब्रदरहुड की ताकत तो थी परन्तु उन्हें सेना की तरह का नैतिक प्राधिकार मिश्र के समाज में हासिल नहीं था। सेना कब तक इस नैतिक प्राधिकार को बनाकर रख पाती है यह तो भविष्य ही बतायेगा।

आइये, अब मिश्र के 2011-13 के जनविद्रोह के समय विभिन्न वर्गों और तबकों द्वारा निभायी गयी भूमिका की चर्चा करें।

IV
जनविद्रोह के दौरान विभिन्न वर्गों व तबकों की भूमिका

मार्क्सवाद हमें सिखलाता है कि यदि किसी समाज में क्रांतिकारी उथल-पुथल हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि कोई ऐसी सामाजिक आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी पूर्ति जीर्ण पड़ चुके संस्थान नहीं होने दे रहे हैं। जितना ही जीर्ण पड़ चुके संस्थान इस सामाजिक आवश्यकता का दमन करने की कोशिश करते हैं उतनी ही तीव्रता से सामाजिक आवश्यकता अपने को प्रकट करती है और उन बंधनों को जब तक तोड़ा नहीं जाता तब तक सामाजिक आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। और तब तक समाज उथल-पुथल के दौर से गुजरता है।

मार्क्सवाद की उपरोक्त बात को यदि हम मिश्र के समाज पर लागू करते हैं तो हम पाते हैं कि होस्नी मुबारक की तानाशाही के खिलाफ पूरे मिश्र के समाज में वर्षों से आक्रोश था।

वहां सामाजिक आवश्यकता अपने को दो रूपों तात्कालिक और दीर्घकालिक के रूप में अभिव्यक्त कर रही थी। तात्कालिक आवश्यकता जहां मुबारक की तानाशाही के खात्मे और पूंजीवादी जनवाद की स्थापना के रूप में तो दीर्घकालिक आवश्यकता पूंजीवाद के स्थान पर समाजवादी समाज की स्थापना की मांग कर रही थी। पहली सामाजिक आवश्यकता प्रत्यक्ष व मुखर थी जबकि दूसरी आवश्यकता अप्रत्यक्ष और उन मांगों के रूप में व्यक्त हो रही थी जो वर्तमान सामाजिक दायरे में पूरी ही नहीं हो सकती थीं।

इस बात की आवश्यकता पैदा हो चुकी थी कि इस तानाशाही का अंत हो और कम से कम वह जनवाद स्थापित हो जो दुनिया के अधिकांश देशों में प्रचलित है। पूंजीवादी जनवाद की मांग मुबारक की तानाशाही के खात्मे की लोकप्रिय मांग के रूप में सामने आयी। मुबारक ने जनाक्रोश को दबाने की जितनी कोशिश की उतना ही वह बढ़ता गया। अंततः मुबारक को जाना पड़ा परन्तु सामाजिक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। मुबारक के बाद मुर्सी की बलि भी इस सामाजिक आवश्यकता ने ले ली परन्तु वह अभी भी पूरी नहीं हो सकी। मिश्र का समाज जिस उथल-पुथल के दौर से वर्ष 2011 से गुजरा है वह अभी भी जारी है। अल सिसी इस आवश्यकता की पूर्ति के नाम पर नये प्रपंच रच रहा है।

मिश्र के समाज में मची उथल-पुथल के दौरान मिश्र के समाज का कोई भी वर्ग या तबका नहीं था जो इस दौरान अपने हितों के लिए सक्रिय न हो। हर वर्ग ने इस उथल-पुथल में हिस्सेदारी की और जाहिर सी बात है हर वर्ग की अपनी इच्छायें आकांक्षायें थी। और हर वर्ग की अपनी विशिष्ट सीमायें भी थीं। मिश्र के समाज में पैदा हुई इस सामाजिक आवश्यकता के लिए हर वर्ग की पहुंच भिन्न थी। विभिन्न पार्टियां, संगठन, समूह विविध तरीकों से अपनी इच्छायें, आकांक्षायें व हितों को व्यक्त कर रहे थे। हर वर्ग घटनाक्रम में अपना ही रंग भरना चाहता था। इस कारण संघर्ष बहुविध रूप धारण कर रहा था। तहरीर चौक इस घटनाक्रम के मुख्य रंगमंच के रूप में उभरा। वहीं से देश का राजनैतिक भविष्य तय हो रहा था। तहरीर चौक में एक तरह से देश की सभी सामाजिक शक्तियों के प्रतिनिधि मौजूद थे परन्तु वहां बहुलता थी युवाओं की। और ये युवा मिश्र के मजदूर-मेहनतकश वर्ग की पृष्ठभूमि से आये हुए थे। वे आधुनिक तकनीक से लैस थे, वे भविष्य के प्रति उत्साही थे और वे संगीनों का बेखौफ होकर सामना कर रहे थे।

मिश्र के समाज में मची उथल-पुथल के दो ध्रुव थे या हैं। मिश्र का पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग और बाकी वर्ग और तबके इन दो ध्रुवों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अपनी सीमाओं के साथ कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर ढुलक रहे थे। मजदूर वर्ग से जहां परिवर्तन, बदलाव या क्रांति की पुकार आती थी वहीं पूंजीपति वर्ग और यहां तक उसके पीठ पर हाथ रखने वाला साम्राज्यवाद स्थिरता, स्थायित्व या 'क्रांति का काम हो चुका' जैसी बातें कर रहा था। पूंजीपति वर्ग बार-बार कह रहा था, "काम पर वापस लौटो" तो मजदूर वर्ग कह रहा था "यह कार्यवाही का समय है।" हिलेरी क्लिंटन से लेकर मुर्सी व अब अल सिसी का नारा या आम जनों को उपदेश यही रहा है कि वे काम पर वापस लौटें और सामान्य जीवन शुरू करें ("Get back to work to get paid and life to get back to normal")। इन नारों या उपदेश के बावजूद मजदूर वर्ग लगातार संघर्षरत रहा और अब स्थिति यह है कि अल सिसी हड़ताल, धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाने का पूरा इंतजाम करने के लिए मुबारक के जमाने के काले कानूनों और अफसरों को नये रंग रोगन के साथ वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नये 'विरोध कानून' (Protest Law) का मकसद मिश्र के समाज से उस जनवाद को छीन लेना है जो शासकों की इच्छा के विरुद्ध और उन से संघर्ष करके आम जन ने हासिल किया था। इसी तरह संविधान का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है वह सामाजिक उथल-पुथल के दौर में मिश्र की जनता के द्वारा हासिल जनवाद को षड्यंत्रकारी ढंग से छीन लेने की कवायद है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मिश्र के शासक वर्ग के असली निशाने पर मजदूर वर्ग है। हालांकि फिलहाल संघर्ष के निशाने पर मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक कट्टरपंथी थे परन्तु एक बार उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल देने के बाद प्रथम नहीं द्वितीय रक्षापंक्ति के रूप में उनकी भूमिका को सुनिश्चित कर लेने के बाद शासक वर्ग अपनी पूरी ताकत के साथ मजदूर वर्ग पर तीखा और बड़ा हमला बोलेगा।

अब विभिन्न वर्गों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करें।

पूंजीपति वर्ग

दुनिया के अन्य देशों की तरह मिश्र का पूंजीपति वर्ग समांग नहीं है। उसमें किस्म-किस्म के बंटवारे हैं। एकाधिकारी- गैर एकाधिकारी, औद्योगिक-कृषि- व्यापारी, नौकरशाह इत्यादि। इन बंटवारों के अनुरूप मिश्र के शासन तंत्र में इस बात का स्थान (स्पेस)

उपलब्ध नहीं रहा है कि विभिन्न गुट आपस में खुली सौदेबाजी कर सकें, राजनैतिक पार्टियों का गठन कर सकें, सत्ता में हिस्सेदारी कर सकें।

गणतंत्र की स्थापना के बाद से ही मूलतः सेना और सरकार से घनिष्ठता से जुड़े एकाधिकारी घरानों और नौकरशाह पूंजीपतिवर्ग के हाथ में सत्ता रही है। होस्नी मुबारक की पार्टी-नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (एन.डी.पी.) ही एकमात्र कानूनी राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना अनवर सादात ने अपने शासन काल के दौरान की थी। यह दल क्रांति का पथ छोड़ चुके कम्युनिस्ट पार्टी खासकर सामाजिक फासीवादी जमाने की सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीकों की नकल करता था। इस दल में मिश्र के किस्म-किस्म के प्रतिक्रियावादी तत्वों की भरमार थी यद्यपि यह अपने स्वरूप को औपचारिक तौर पर धर्म निरपेक्ष किस्म का होने का दावा करता था। एकाधिकारी घरानों और नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के गठजोड़ के द्वारा शासित मिश्र के समाज में अन्य पूंजीपति वर्ग के हिस्सों के लिए जो स्थान उपलब्ध था वह इसी राजनैतिक दल के दायरे के भीतर था। किसी भी दल, संगठन या राजनैतिक समूह की स्थापना पर कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ था। सैन्य शासक अपने विरोधियों से सख्ती से निपटते थे। राजनैतिक हत्यायें और गैर कानूनी ढंग से लोगों को बंदी बनाया जाना आम था। होस्नी मुबारक के समय सेना को पृष्ठभूमि में धकेल कर सीक्रेट पुलिस का गठन किया गया। ऐसा करने के पीछे यह भी मकसद था कि सेना की ऐसी छवि बनाकर रखी जा सके कि वह देश भक्ति सहित श्रेष्ठ मूल्यों की वाहक व नैतिकता की प्रतिमूर्ति है। उसका नैतिक प्राधिकार बना रहे। बाद के घटनाक्रम ने शासक वर्ग की इस चाल को कामयाब भी साबित किया।

सीक्रेट पुलिस सुरक्षा व आतंकवाद के खात्मे के नाम पर घोर अत्याचार का पर्याय बन चुकी थी। पुलिस के पास असीमित अधिकार थे और उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने या न्याय की गुहार लगाने के लिए सामान्य तंत्र का अभाव था।

नौकरशाह पूंजीपति वर्ग और एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग आपस में असंख्य सूत्रों से बंधे हुए थे। होस्नी मुबारक के शासन काल में मिश्र के पूंजीवाद ने तीव्र गति से विकास किया था। उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण की नीतियों से इस वर्ग ने अकूत दौलत हासिल की थी। अमेरिकी साम्राज्यवाद सहित पश्चिमी साम्राज्यवादियों से मिलने वाली सहायता से इस वर्ग की दौलत में विभिन्न ढंग से इजाफा हो रहा था। सेना, जो कि मिश्र की अर्थव्यवस्था के एक चौथाई हिस्से से भी अधिक को नियंत्रित करती है, के अधिकारी अकूत दौलत के स्वामी बन चुके थे।

मिश्र के राज्य और एकाधिकारी घरानों के घनिष्ठ सम्बंधों और उनके लगातार एकीकरण के साथ मिश्र राजकीय पूंजीवाद की घृणित मिसाल बन चुका था। राजकीय पूंजीवाद और उसकी शासन प्रणाली के रूप में एक दलीय शासन वाली सैन्य तानाशाही के दमन के नीचे मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग ही नहीं बल्कि पूंजीपति वर्ग का गैर वरीयता व अधिकार प्राप्त हिस्सा भी कसमसा रहा था। यद्यपि शासन तंत्र से इस उपेक्षित पूंजीपति वर्ग की एक आवाज मुस्लिम ब्रदरहुड के रूप में मौजूद थी।

मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिश्र के नौकरशाह व एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के रिश्ते नरम-गरम थे। ब्रिटिश काल में इसे एक सुरक्षा पंक्ति के रूप में विकसित किया गया। मुस्लिम ब्रदरहुड क्योंकि खुले तौर पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता था इसलिए उसने धार्मिक कार्यों के साथ सामाजिक सेवाओं के जरिये देशव्यापी सशक्त नेटवर्क का निर्माण किया हुआ था। सैन्य तानाशाहों से सीधी टकराहटों से वह मुर्सी के शासन के पतन के पहले तक हमेशा बचता रहा। शासक वर्ग का यह घोर प्रतिक्रियावादी धड़ा चुपचाप अपनी तैयारियों में लगा रहा और अपनी बारी की प्रतीक्षा करता रहा।

होस्नी मुबारक के खिलाफ उमड़े जनाक्रोश ने, जिसने बाद में जनविद्रोह का रूप ले लिया था, मुस्लिम ब्रदरहुड को यह मौका दे भी दिया। मुर्सी ने अपने एजेण्डे को लागू करने की जल्दबाजी में एक के बाद एक ऐसी गलतियां कर दीं कि वे जल्द ही आम जनता के साथ एकाधिकारी घरानों और नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के गठजोड़ के कोपभाजन का शिकार बन गये। जून 2013 के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड को अपने जीवनकाल में सबसे बुरे दिन देखने पड़े। हजारों की संख्या में उसके सदस्यों व समर्थकों की हत्या सेना और पुलिस द्वारा कर दी गई। उसके प्रमुख नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। भविष्य में धार्मिक व कट्टरपंथी संगठनों की राजनीति में भागीदारी करने से रोकने के लिए कठोर कानून बनाये जाने लगे। मुस्लिम ब्रदरहुड को दोयम दर्जे की स्थिति और दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में उसकी भूमिका तक ही सीमित करने के प्रयास साम्राज्यवाद और अरब शेखशाहियों के दबाव के बीच फिलवक्त शासक वर्ग का एकाधिकारी व नौकरशाह गठजोड़ वाला हिस्सा कर रहा है।

मुस्लिम ब्रदरहुड को मूलतः मिश्र के बड़े व्यापारिक समूहों का ऐसा संगठन कह सकते हैं जिसका शहरी व ग्रामीण व्यापारी वर्ग के दृढ़ आधार के साथ बड़े-छोटे किसानों व शहरी-ग्रामीण निम्न मध्य वर्ग का सक्रिय व स्थिर समर्थन प्राप्त रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा खाद्य व प्राकृतिक संकटों के समय की गई कार्यवाहियों व खासतौर पर बांटी गयी खैरात ने उसे लोकप्रिय बनाया है। सामाजिक सेवाओं और खैरात बांटने के लिए उसे धन मिश्र के शासक वर्ग के व्यापारिक व कृषि हिस्से के अलावा अरब की शेखशाहियों से प्रचुर मात्रा में मिलता रहा है। मिश्र के सुन्नी बहुल देश में जहां सूफी सम्प्रदाय के विचारों का मूलतः बोलबाला रहा हो वहां मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता व कार्यकर्त्ता आधुनिक वेशभूषा में कट्टर इस्लाम के प्रचारक व समर्थक थे। शहरी, शिक्षित, पेशेवर व व्यापारिक समूह से इसे वे नेता और कार्यकर्त्ता मिलते रहे हैं जो पहली निगाह में कट्टर धार्मिक व फासिस्ट विचारों के लग ही नहीं सकते थे।

मुस्लिम ब्रदरहुड के सामाजिक एजेण्डे के अलावा आर्थिक एजेण्डा कमोबेश वही था जो मुबारक का था। मुर्सी ने अपने शासनकाल में यह साबित करने की कोशिश भी की। इस विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे उसके आर्थिक एजेण्डे ने

उनके पतन को तीव्रता प्रदान की और कैसे आम जनता का एक बड़ा हिस्सा ही नहीं सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ सेना भी उनके खिलाफ हो गयी थी। और कैसे सत्ता संभालने के बाद सैन्य नियंत्रित सरकार ने अपने आधार व साख को बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाये जो नव उदारवाद के इस काल में बेहद गलत माने जाते हैं।

लोकप्रिय जनांदोलन की लहर पर सवार होकर एक षड्यंत्रकारी ढंग से सत्ता पर अब पुनः नौकरशाह पूंजीपति व एकाधिकारी पूंजीवादी घरानों का गठजोड़ काबिज हो चुका है। होस्नी मुबारक व मुर्सी को खलनायक साबित करने में जुटे अल सिसी में नासिर की छवि ढूंढने व गढ़ने के लिए पूरी कोशिश ऐसे लोगों द्वारा की जा रही है जो अपने को नासिरवादी कहते हैं। नासिरवाद के तथाकथित इस नये अवतार को मिश्र के समाज में तथाकथित वामपंथियों, सोशलिस्टों व ट्राट्स्कीपंथियों के साथ एन.जी.ओ. का भी समर्थन हासिल है। ऐसे ही भिन्न-भिन्न किस्म के तत्वों से सज्जित तामारोड (विद्रोह) को मुर्सी के पतन के बाद सत्ता पर काबिज या पुनर्स्थापित गठजोड़ का भरपूर समर्थन व नेतृत्व मिला था।

अब यह गठजोड़ 2012-13 के जनविद्रोह से सबक सीख कर ऐसी बुर्जुआ तानाशाही स्थापित करना चाहता है जो रूप में तो संसदीय लोकतंत्र का रूप धारण करे परन्तु अंतर्वस्तु में उन्हीं सारे गुणों से लैस हो, जो कि मिश्र के आधुनिक इतिहास की विशेषता है। नासिर, सादात व मुबारक काल का शासन तो हो परन्तु संसदीय लोकतंत्र के मिश्र की नयी हासिल विशेषताओं के साथ और जहां तक मुस्लिम ब्रदरहुड वाले पूंजीवादी गुट का प्रश्न है उसके साथ पर्दे के पीछे सुलह-समझौते की कोशिश जारी है। मिश्र का शासक वर्ग किसी भी सूरत में अपनी इस दूसरी सुरक्षा पंक्ति को नहीं त्याग सकता है। और वे ऐसा न करें इसमें साम्राज्यवाद के हितों का भी दबाव है।

निम्न पूंजीपति वर्ग

मिश्र का निम्न पूंजीपति वर्ग भी कोई समांग वर्ग नहीं है। इसमें शहर और देहात की विशाल आबादी शामिल है। शहरी-ग्रामीण दुकानदार, वकील-शिक्षक- डॉक्टर जैसे पेशेवर, सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के छोटे-मझोले अफसर व कर्मचारी, मझोले व छोटे किसान आदि से यह वर्ग निर्मित है। इस वर्ग के सामने चुनौतियां त्यों-त्यों बढ़ने लगी ज्यों-ज्यों मिश्र की अर्थव्यवस्था का संकट वर्ष 2008 से विशेष तौर पर गहराने लगा।

मिश्र के निम्न पूंजीपति वर्ग के एक हिस्से ने अनवर सादात और खास तौर पर मुबारक के काल में हुयी तीव्र पूंजीवादी प्रगति और नव उदारवादी नीतियों का लाभ उठाया था। इसके एक हिस्से को देश से बाहर खाड़ी देशों में अपने विशिष्ट पेशों और कौशल से होने वाली आय का भी लाभ मिला था। यह हिस्सा परम्परागत मध्य वर्ग के उस हिस्से से भिन्न रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व सरकारी नौकरियों के दम पर सम्पन्न हुआ था। मुबारक के तीव्र निजीकरण के दौर में परम्परागत मध्य वर्ग का हिस्सा संकट के दायरे में तेजी से आने लगा परन्तु नव उदारवादी नीतियों से लाभ उठाने वाले तबके के सामने संकट 2008 के बाद ही आना शुरू हुआ। इस नवोदित वर्ग की क्षुब्धता तब और बढ़ जाती थी जब ये अपने देश में सामान्य जनवाद का अभाव पाते थे। नब्बे के दशक में और फिर इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में संचार व सूचना क्रांति ने इसे अपनी क्षुब्धता व्यक्त करने का ऐसा साधन इण्टरनेट के रूप में मुहैय्या करा दिया जिस पर मुबारक ने जनवरी 2011 में तब प्रतिबंध लगाया जब उसने अपनी भूमिका जन विद्रोह को प्रस्फुटित करने में काफी अच्छे ढंग से निभा दी थी। मुबारक के इस प्रतिबंध ने आग में घी का काम किया था।

मुबारक के शासन के खिलाफ निम्न पूंजीपति वर्ग के लगभग सभी हिस्से सक्रिय रहे। परम्परागत मध्य वर्ग और नव उदारवादी नीतियों से लाभ उठाने वाले वर्ग ने लोकप्रिय जन कार्यवाहियों के प्रचार व संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। बेरोजगारी और अनिश्चित भविष्य से क्षुब्ध युवा नयी संचार तकनीक का इस्तेमाल कर होस्नी मुबारक के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर रहे थे जिससे निपटने के मुबारक के हर तरीके भोथरे और आक्रोश को और बढ़ाने वाले साबित हो रहे थे। मुबारक की तरह लोकतंत्र को देर से लागू करने पर सेना और बाद में मुर्सी के अधिनायकवादी कदमों का भी इस वर्ग के एक हिस्से ने पुरजोर विरोध किया। यहां यह बात विशेष तौर पर गौर करने की है यह वर्ग मुबारक के विरोध करने में जितना एकजुट था उतना मुर्सी के विरोध के समय नहीं था। यह वर्ग दो विशाल शिविरों में बंट चुका था। कारण यह था कि मुस्लिम ब्रदरहुड का इस वर्ग के एक बड़े हिस्से में दशकों से खासा प्रभाव था। और यही नहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का देहाती क्षेत्रों में व्यापक असर रहा है। इसीलिए मुर्सी के शासन के खिलाफ देहातों और छोटे शहरों-कस्बों में उतने व्यापक प्रदर्शन नहीं हुए जितने मुबारक के खिलाफ हुए थे। इसके उलट देहातों तथा छोटे शहरों-कस्बों में ही नहीं बल्कि काहिरा सहित बड़े शहरों के निम्न पूंजीपति वर्ग के इलाकों में मुर्सी को अपदस्थ करने व ब्रदरहुड के दमन का तीव्र विरोध हुआ। जुलाई 2013 में मारे जाने वालों में भारी संख्या ऐसे ही लोगों की थी। मुर्सी की नीतियों ने मध्य वर्ग के परम्परागत हिस्से को आक्रोशित कर दिया था। सरकारी कर्मचारियों के मुर्सी के शासन के खिलाफ होने के कारणों की पहले ही चर्चा की जा चुकी है। निम्न पूंजीपति वर्ग की विभाजन की यह स्थिति अब भी बनी हुई है।

निम्न पूंजीपति वर्ग के बीच साम्राज्यवाद द्वारा पोषित विचारों और गैर सरकारी संगठनों की भी अच्छी खासी घुसपैठ रही है। जनवाद के ढेरों विचार पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों द्वारा फैलाये जाने वाले वैचारिक प्रदूषण से भरे हुए थे। असल में पश्चिमी साम्राज्यवादियों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की हिफाजत और अपने घनिष्ठ सहयोगी देशों में हितों की सुरक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क के जरिये एक और सुरक्षा पंक्ति का निर्माण हाल के वर्षों में कर लिया गया है। इस सुरक्षा पंक्ति के लिए पूंजीवादी व्यवस्था

परम पवित्र वस्तु और अंतिम व निर्णायक व्यवस्था है। भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद से मुक्त पूंजीवाद इनके लिए आदर्श है। इस आदर्श को लोकप्रिय बनाने में ये संस्थायें रात दिन एक कर देती हैं। पूर्व सोवियत संघ के देशों में नब्बे के दशक की 'रंगीन क्रांतियों' की तरह मिश्र के जनविद्रोह को समेटने के लिए ये रात दिन मंसूबे बांधती रही हैं। मुबारक और मुर्सी के पतन में इनकी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता परन्तु इनकी भूमिका को बढ़ा-चढ़ा कर देखना मिश्र के समाज के यथार्थ और आम जनता की भूमिका को नजरअंदाज करना होगा। मिश्र में हुआ जनविद्रोह साम्राज्यवाद के द्वारा प्रायोजित व नियंत्रित नहीं था यद्यपि वह इसके लिए लगातार प्रयासरत रहा। वह जन विद्रोह को एक जगह खासकर मुबारक के पतन के बाद मुर्सी के शासन तक सीमित कर देना चाहता था परन्तु उसकी सारी योजनायें व समीकरण मिश्र के समाज में चल रहे वर्ग संघर्ष के कारण बिगड़ व उलझ गये।

मुबारक के शासन के खिलाफ आक्रोश काफी लम्बे समय से पनप रहा था। वर्ष 2006 से साम्राज्यवाद द्वारा पोषित गैर सरकारी संस्थाओं सहित स्वत:स्फूर्त ढंग से अनेकों संगठन अस्तित्व में आने लगे थे। ' सिक्स्थ अप्रील मूवमेंट,' 'ट्वन्टीयूथ मार्च मूवमेंट,' 'नाइन्थ मार्च मूवमेंट फॉर दि इण्डिपेन्डेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज,'' ईजीप्सियन मूवमेंट फॉर चेंज, वूमेन फॉर चेंज,'दि कोआर्डिनेशन कमेटी फॉर दि डिफेंस ऑफ वर्कर्स राइट,' कमेटी फॉर दि डिफेंस ऑफ इंशोरेंस फण्ड्स,' 'सेण्टर ऑफ मेन्यूअल वर्कर्स ऑफ ईजिप्ट,' 'फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स,' इन्जीनियर्स अंगेस्ट सीक्वेस्ट्रेशन (Sequestration)', 'दि महल्ला कमेटी फार वर्कर्स कन्सीयसनेस (Consciousness),' 'वर्कर्स फॉर चेंज इत्यादि (स्रोत: Arab spring libeyan Winter by Vijay Prashad)।

मुर्सी के शासन के पतन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला संगठन 'तामारोड' ऐसे ही भांति-भांति किस्म के संगठनों व संस्थाओं का संयुक्त मोर्चा था। तामारोड में इन संगठनों के अलावा कई विचारधाराओं के लोग भी अपने संगठनों या पार्टी के साथ शामिल थे। इन लोगों व संगठनों में नासिरवादी, मुबारकपंथी, सोशलिस्ट, ट्राट्स्कीपंथी, सोशल डेमोक्रेट आदि-आदि शामिल थे।

मजदूर वर्ग

मिश्र के समाज में आबादी की दृष्टि से मजदूर वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। कमोबेश यह उसी तरह से समाज का सबसे बड़ा वर्ग बना जिस तरह की प्रक्रियाओं से तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में बनता जा रहा है। मिश्र की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा इक्कीसवीं सदी आते-आते महज 14-15 फीसदी रह गया था। इसी तरह कृषि क्षेत्र में लगी आबादी का प्रतिशत गिर कर 32 फीसदी रह गया है। भारत की तरह मिश्र में जो आबादी कृषि क्षेत्र में सक्रिय है उसका बड़ा हिस्सा किसान नहीं बल्कि खेतीहर सर्वहारा ही बनता है। मिश्र की कामगार आबादी का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है। उद्योगों में मिश्र की आबादी का यद्यपि महज 17 फीसदी ही लगा हुआ है परन्तु इस क्षेत्र के मजदूरों ने अपने संघर्षों के दम पर न केवल 2011 के जनविद्रोह की नींव रखी बल्कि इस विद्रोह के दौरान और उसके बाद भी निरंतर संघर्षरत रहे। मिश्र के मजदूर वर्ग की संघर्षशीलता और संघर्षों की निरंतरता से आतंकित अल सिसी की सरकार तो मुबारक कालीन कानूनों को नया रंग रूप प्रदान (नये प्रोटेस्ट लॉ द्वारा) कर रही है।

औद्योगिक मजदूरों के संघर्षों सिलसिला अभी भी बना हुआ है परन्तु औद्योगिक मजदूरों के बीच नई सरकार की नीतियों व संविधान के प्रारूप को लेकर विभाजन बढ़ गया है। जहां मजदूरों का एक हिस्सा खासकर अभिजात हिस्सा मोटे तौर पर नई सरकार के साथ है वहीं दूसरा हिस्सा अपनी मांगों के साथ संघर्षरत है।

अल सिसी की सरकार ने मजदूर वर्ग के संघर्षों के दबाव तथा दहाई अंकों में पहुंच चुकी मुद्रास्फीति (अगस्त 2013 में शहरी मुद्रास्फीति की दर 9.7 फीसदी) के बीच घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को करीब 700 ई.जी.पी. से बढ़ाकर 1200 ई.जी.पी. कर देगी। और यह वृद्धि जनवरी 2014 से लागू की जायेगी। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मजदूरों के बीच के फर्क को उनकी न्यूनतम मजदूरी से भी समझा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की औसत न्यूनतम मजदूरी 657 ई.जी.पी. है तो निजी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी 397 ई.जी.पी. है। निजी क्षेत्र के मजदूर लम्बे समय से अपनी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने व बोनस में हिस्सेदारी की मांग करते रहे हैं। यह संघर्ष जारी है।

मिश्र में होस्नी मुबारक के समय से कार्यरत केन्द्रीय संगठन ईजिप्शियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन (ई.टी.यू.एफ.) के नेतृत्व पर सेना का प्रभाव रहा है। इस संगठन ने बाद के समय में होस्नी मुबारक का विरोध किया था और 2011 के जनविद्रोह में हिस्सेदारी की थी। मुर्सी के शासन का भी विरोध किया परन्तु जब से सेना नियंत्रित सरकार का गठन हुआ है इसकी भूमिका सरकार की नीतियों के समर्थन में खुलकर मजदूर विरोधी हो गई है। यह सरकार नियंत्रित संस्थानों से लेकर निजी संस्थानों में मजदूरों के संघर्षों व उनकी मांगों को दबाने में सरकार के साथ घृणित सहयोग कर रही है। यह नव उदारवादी नीतियों का समर्थक रही है।

ई.टी.यू.एफ. की तरह ही होस्नी मुबारक के शासन के खिलाफ फूटे जन विद्रोह के समय अस्तित्व में आयी यूनियन 'ईजिप्शियन फेडरेशन ऑफ इनडिपेंडेंट यूनियन (ई.एफ.आई.टी.यू.)' की भूमिका भी अब नकारात्मक हो चुकी है। ई.एफ.आई.टी.यू. अपने को स्वतंत्र यूनियन के रूप में प्रचारित करता है परन्तु इस यूनियन को अमेरिकी साम्राज्यवादियों का वरदहस्त प्राप्त रहा है। इसके नेता कमाल अबू ईटा वर्तमान सरकार में श्रम मंत्री (Man power Minister) हैं। यह स्वतंत्र यूनियन 'तामारोड' की सदस्य भी रही है।

इन दो प्रमुख ट्रेड यूनियन सेण्टर के अलावा मजदूर वर्ग के बीच कई गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) भी सक्रिय रहे हैं। इनमें 'दि को आर्डिनेशन कमेटी फॉर दि डिफेंस ऑफ वर्कर्स राइट','सीरियस वर्क एसोसिएशन (एस.डब्ल्यू.ए.)','वर्कर्स फॉर चेंज,'

'सेण्टर ऑफ मेन्यूअल वर्कर्स ऑफ दि ईजिप्ट', 'दि सेण्टर फॉर ट्रेड यूनियन एण्ड वर्कर्स सर्विसेज' (CTUWS) आदि प्रमुख रहे हैं। इन संगठनों के पीछे देशी-विदेशी पूंजी सक्रिय है।

मिश्र के मजदूर वर्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित क्रांतिकारी पार्टी के अभाव का होना है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा पर आधारित देशव्यापी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के अभाव के कारण मिश्र के मजदूर वर्ग के पास सही नेतृत्व नहीं रहा है। यद्यपि मिश्र में हाल के वर्षों में कई ऐसी पार्टियां रही हैं जो मजदूर वर्ग के बीच सक्रिय रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी आदि पार्टियां मजदूर वर्ग के बीच विचारधारात्मक विभ्रम फैलाने के काम में ही लगी रही हैं। विभिन्न किस्म के संशोधनवादी विचारों से लैस ये पार्टियां मजदूर वर्ग को पूंजीवाद के दायरे में बांधे रखने का काम कर उसके हितों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से शासक वर्ग की सेवा ही करती रही हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 'तामारोड' में इनकी उपस्थिति और 'तामारोड' द्वारा अल-सिसी सरकार की निर्लज्ज पैरोकारी में दिखायी देता है। यही स्थिति 'तामारोड' में शामिल गैर सरकारी संगठनों की है जो मजदूर वर्ग या अन्यों में सक्रिय हैं। इन पार्टियों और संगठनों का अल सिसी के नेतृत्व में सैन्य तख्ता पलट के समर्थन का मूल तर्क इस्लामिक कट्टरपंथियों को रोकना व खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड के शासन का विरोध रहा है। यह मजदूर वर्ग में सक्रिय तथाकथित वाम पार्टियों की गलत समझ व नीति है कि वे शासक वर्ग के एक गुट के विरोध में शासक वर्ग के दूसरे गुट का समर्थन करके मिश्र के समाज में मजदूर वर्ग के हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह असल में शासक वर्ग के हाथ का खिलौना बनना है। यह मजदूर वर्ग का शासक वर्ग के सामने समर्पण करवाना है।

मजदूर वर्ग के एक हिस्से में इस्लामिक कट्टरपंथियों खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड का भी असर रहा है। यह हिस्सा देहाती सर्वहारा और शहरी मजदूरों के ऐसे हिस्से से बना हुआ है जो व्यापार जैसे क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं। अर्द्ध सर्वहारा और 'स्व रोजगार प्राप्त' व बेरोजगार मजदूरों के बीच में मुस्लिम ब्रदरहुड की लोकप्रियता उसके द्वारा किये जाने वाले सुधारवादी कार्यक्रमों और आपदा के समय बांटी जाने वाली खैरात के कारण रही है। इसलिए जो मजदूर वर्ग होस्नी मुबारक के समय उसके तानाशाही पूर्ण शासन के खिलाफ एकजुट था वह मुर्सी के शासन के खिलाफ संघर्ष के समय विभाजित था। आज अब अल-सिसी की सरकार के समय भी उसके बीच राजनीतिक विभाजन है। उपरोक्त सब कुछ के बावजूद मिश्र के समाज में मजदूर वर्ग की भूमिका खासकर उसके सबसे आगे बढ़े हिस्से औद्योगिक मजदूर वर्ग की भूमिका के बिना उस झंझावात की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसने अल्पकाल में दो राष्ट्रपतियों को अपना पद छोड़ने को मजबूर कर दिया और अल-सिसी की सरकार को 'नागरिक सरकार' का मुखौटा पहनने और शीघ्रातिशीघ्र नये संविधान और नये चुनाव को मजबूर कर दिया है।

2011-13 के जनविद्रोह के दौरान मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा महल्ला टैक्सटाइल के मजदूरों के जुझारू संघर्षों को संज्ञान में लिये बगैर अधूरी है। महल्ला वेविंग एण्ड टैक्सटाइल कम्पनी (Mahalla Weaving and textile company) मिश्र की एक विशाल कम्पनी है जिसमें करीब 22,000 मजदूर काम करते हैं। मुबारक के शासन के समय वर्ष 2006 व वर्ष 2008 में जुझारू हड़तालें करके महल्ला के मजदूरों ने उन आंदोलनों की नींव रखी जो वर्ष 2010 व 2011 में फूटे। मुबारक के शासन के बाद मुर्सी के शासन के खिलाफ भी महल्ला के मजदूरों का संघर्ष बेमिसाल रहा है। मुर्सी के खिलाफ संघर्ष के दौरान महल्ला कस्बे के मजदूरों व विद्यार्थियों ने महल्ला कस्बे को मुर्सी शासन से 'स्वायत्त' (autonomous) घोषित कर दिया था। अल-सिसी की सरकार को भी महल्ला के मजदूरों ने अपने जुझारू तेवर से झुकने को मजबूर कर दिया था। अक्टूबर 2013 में तीन दिन की हड़ताल के बाद अल-सिसी की सरकार को मजदूरों की लाभ हिस्सेदारी पर आधारित बोनस (Profit sharing bonus) की घोषणा करनी पड़ी। महल्ला के मजदूरों के संघर्ष के दायरे में मूलतः राजनीतिक व आर्थिक लड़ाईयां रही है परन्तु ये संघर्ष वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के दायरे में ही सिमटने को मजबूर रहे हैं। मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के अभाव में जुझारू से जुझारू संघर्षों को जन्म देने वाला आंदोलन भी पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ों को हिला तक नहीं पाता है। महल्ला मजदूरों के जुझारू संघर्ष व तेवर यद्यपि मिश्र के मजदूरों के संघर्षों में सबसे ऊपर व प्रभावकारी रहा है परन्तु यह इस बात का भी सबक दुनिया भर के मजदूरों के सामने पेश करता है कि मजदूरों के संघर्षों का हस्र बिना क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के क्या हो जाता है। हालांकि मिश्र के मजदूरों उसमें औद्योगिक मजदूरों और उसमें भी महल्ला सहित टैक्सटाइल व वस्त्र निर्माण के मजदूरों ने अपने संघर्षों के जरिये मजदूर वर्ग के जुझारूपन व सम्भावनाशीलता का शानदार उदाहरण पेश किया है।

युवा और महिलायें

मिश्र में 2011-13 के जनविद्रोह के दौरान युवा और महिलाओं की भागीदारी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तहरीर चौक में क्रांतिकारी रौनक युवा और महिलाओं के कारण ऐसी छायी कि होस्नी मुबारक और मुर्सी के शासन के खिलाफ हुए संघर्षों के सैकड़ों दृश्य पूरी दुनिया की स्मृति में अमिट हो गये। युवाओं के जोश ने जहां होस्नी मुबारक और मुर्सी के शासन को कड़ी चुनौती पेश की वहीं महिलाओं की भागीदारी ने उनके शासक बने रहने के औचित्य पर ही प्रश्न खड़े कर दिये। समाज के इन महत्वपूर्ण तबकों की विद्रोह में भागीदारी और सक्रियता ने मिश्र के शासकों के हाथ-पांव फुला दिये और मिश्र इतिहास के उस अनूठे दौर से गुजरा जिसमें दो वर्ष के भीतर ही पहले मुबारक फिर सेना और फिर मुर्सी को सत्ता छोड़नी पड़ी। और आज भी इन तबकों की सक्रियता ने मिश्र के समाज में गति बनाकर रखी हुई है।

मिश्र में महिलाओं की सामाजिक सक्रियता अरब दुनिया की महिलाओं की जनवाद और मुक्ति की आकांक्षा का प्रतिनिधिक स्वर बनकर उभरी। मिश्र की महिलाओं को सामाजिक संघर्ष में भागीदारी की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। होस्नी मुबारक के पतन के बाद समाज की प्रतिक्रियावादी ताकतें उनके ऊपर हमलावर हो गईं। मुर्सी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दौरान महिलाओं पर यौन हमले किये गये। कई महिलाओं को इस दौरान अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने महिलाओं के खिलाफ दुश्प्रचार के एक से बढ़कर एक अभियान आयोजित किये। इस सबके बावजूद मिश्र की महिलाओं ने न केवल अरब दुनिया बल्कि शेष दुनिया की महिलाओं के मुक्ति आंदोलन के लिए जबरदस्त प्रेरणा का काम किया।

मिश्र के युवा और महिलाओं के बीच वे सभी राजनैतिक व सामाजिक दल व संगठन सक्रिय रहे हैं जिनकी पहले मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है। वैसे भी युवा और महिलायें मुख्यतः इन्हीं वर्गों से आयी भी थीं।

V

साम्राज्यवाद की भूमिका

वर्तमान जन विद्रोह में साम्राज्यवाद की भूमिका की चर्चा से पहले थोड़ा इतिहास के कुछ पृष्ठ उलटें तो हम पाते हैं कि नासिर तीसरी दुनिया के उन शासकों में रहे हैं जिन्होंने पचास के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली थी। सोवियत संघ और अमेरिकी ध्रुवों के बीच बंटी दुनिया में यह तीसरी दुनिया के शासकों का अपने देश में विश्व परिस्थिति का लाभ उठाकर पूंजीवादी विकास का रास्ता था। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के साथ नासिर अरब देशों में ही नहीं बल्कि पूरी तीसरी दुनिया के लोकप्रिय नायकों में शुमार हो गये थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उससे अधिक अरब राष्ट्रवाद के जुझारू तेवरों के साथ नासिर ने अपने देश में विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को एक हद तक पूरा किया था और अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके घनिष्ठ सहयोगी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। इस समय वह सोवियत संघ के करीब था।

1967 में इजरायल के हाथों मिली पराजय के साथ नासिर के अरब राष्ट्रवाद के नारे की चमक कम होने लगी। उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद अनवर सादात के कैम्प डेविड समझौते के बाद मिश्र सोवियत खेमे के बजाय अमेरिकी खेमे के अति निकट हो गया और पश्चिम एशिया के उन देशों में शामिल हो गया जिन्हें सबसे अधिक अमेरिकी सैन्य मदद मिलती रही है। यह मदद अनवर सादात के जमाने से मुर्सी के जमाने तक लगातार जारी रही। बीते दिनों काफी हो-हल्ला मचने और सैन्य तख्ता पलट वाले देशों को सैन्य सहायता न देने वाले अमेरिकी कानून के हवाले के बाद अमेरिका ने वार्षिक सैन्य सहायता पर रोक लगाई। हालांकि यह रोक दिखावटी और वक्ती है। मिश्र की सेना नियंत्रित सरकार के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के निकट सहयोगी अरब देशों की शेखशाहियों ने इस सैन्य सहायता से कई गुने की मदद तुरन्त मुहैय्या करा दी । इस सबके जरिये अमेरिकी साम्राज्यवाद ने एक तीर से दो निशाने साध लिये।

अल-सिसी ने करीब तीन दशक बाद, रूस से पुनः सैन्य आपूर्ति के समझौते कर यह दिखलाने की कोशिश की कि वह किसी भी तरह के दबाव में न होकर अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। अल-सिसी के इस कदम का नासिरवाद के वापसी के रूप में कईयों ने समर्थन किया। मिश्र के भीतर अल-सिसी की लोकप्रियता खासकर मध्य वर्ग में इस कदम से काफी बढ़ी। यद्यपि सच्चाई यह है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ सम्बंधों में इससे कोई खास बदलाव नहीं आया और मिश्र की अमेरिकी साम्राज्यवाद पर रही अति निर्भरता के कारण यह सम्भव भी नहीं है।

अमेरिकी साम्राज्यवाद ने 2011-13 के दौरान अपने घृणित प्रतिक्रियावादी चरित्र के अनुरूप शातिर भूमिका निभायी। वह तब तक होस्नी मुबारक का साथ व उसे संरक्षण प्रदान करता रहा जब तक उसके खिलाफ जनविद्रोह ही नहीं फूट गया। होस्नी मुबारक के दमन चक्र को अमेरिका की हर तरह से मदद मिलती रही। फरवरी 2011 में जनविद्रोह के फूट पड़ने के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादी तरह-तरह से उसमें अवरोध डालते रहे। हर दूसरे दिन मिश्र की विद्रोही जनता को उपदेश देते रहे हैं कि अब उनके द्वारा की गई 'क्रांति' सम्पन्न हो गयी है। अब वे घर और काम पर लौटें तथा सयानों को अब अपना काम करने दें।

मुबारक के पतन के बाद पहले वे सैन्य सरकार फिर तथाकथित लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी मुर्सी सरकार का समर्थन करने लगे। मुर्सी के मिश्र के समाज के इस्लामीकरण की नीतियों का वे समर्थन करते रहे। फिर मुर्सी को सेना द्वारा सत्ता से हटाये जाने के बाद वे सेना का खुला समर्थन करते रहे। कई हफ्तों के बाद उन्होंने माना कि सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकार को हटाकर गलत किया है और तब उन्होंने वार्षिक सैन्य सहायता पर रोक लगायी।

अमेरिकी साम्राज्यवाद ने मिश्र की जनता की पहलकदमी रोकने और उसे दिग्भ्रमित करने के लिए हर तरह के कदम उठाये। मुस्लिम ब्रदरहुड और गैर सरकारी संगठनों के जरिये उसने और मिश्र के शासक वर्ग ने दो भरोसेमंद सुरक्षा पंक्तियों का निर्माण दशकों पूर्व ही कर लिया था। गैर सरकारी संगठनों को पहले से ही प्रशिक्षित व दीक्षित किया जा चुका था कि वे इन परिस्थितियों में क्या और कैसे भूमिका निभायें। गैर सरकारी संगठनों की अति सक्रियता व बड़ी भूमिका की वजह से ही अरब देशों के कई बुद्धिजीवियों ने इसे प्रायोजित क्रांति का नाम दिया था।

असल में अमेरिकी साम्राज्यवादी मिश्र के जनविद्रोह को नियंत्रित व निर्देशित उसी तरह से करना चाहते थे जिस तरह से उन्होंने सोवियत संघ के पूर्व देशों में 'रंगीन क्रांतियों' को किया था परन्तु मिश्र के मजदूरों, युवाओं और महिलाओं ने उनके सारे गणित को बिगाड़ दिया। मुबारक और खासकर मुर्सी का पतन अमेरिकी साम्राज्यवादियों की इच्छा व योजनाओं के खिलाफ था।

2011-13 के पूरे समय के दौरान अमेरिका के सहयोगी अन्य साम्राज्यवादी देश जहां मूलतः अमेरिका के साथ खड़े हो उसकी योजनाओं को परवान चढ़ा रहे थे वहीं रूसी साम्राज्यवादी एक ओर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सीरिया के घटनाक्रम में उनकी भूमिका के कारण बढ़ी हुई साख व मिश्र की जनता में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ बढ़े आक्रोश व नफरत ने उन्हें 2013 में यह मौका दे भी दिया।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों के घनिष्ठ सहयोगी तुर्की, इजरायल, जार्डन सहित शेखशाहियों ने वैसी ही भूमिका निभायी जैसी अमेरिका चाहता था। इस पूरे क्षेत्र में सऊदी अरब तो वहां जा पहुंचा जहां उसने मिश्र की तरह बहरीन व यमन में हुए जनविद्रोह को आतंकवाद के नाम पर सैन्य ताकत के साथ कुचल डाला। इस दौरान अमेरिका सहित साम्राज्यवादी 'स्वतंत्रता,' 'नागरिक सरकार,''लोकतंत्र,' 'मानवाधिकार', जैसे जुमलों को औपचारिक तौर पर भी दोहराना भूल गये।

मिश्र के शासक रूसी साम्राज्यवादियों से निकटता दिखलाकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों से वर्तमान विश्व परिस्थिति में कुछ सौदेबाजी तो कर सकते है परन्तु वे उनके खिलाफ जुझारू तो क्या मरियल प्रतिरोध दिखाने की स्थिति में नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण मिश्र की अर्थव्यवस्था का पश्चिमी विश्व पूंजीवादी व्यवस्था से अत्यधिक एकीकरण है। साथ ही मिश्र की सेना की तकनीक, हथियार व कल पुर्जों आदि को लेकर निर्भरता भी है। मिश्र की सेना के अधिकतर उच्च अधिकारी अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद भी अरब दुनिया में मिश्र जैसे सहयोगी देश व उसकी पूंजी के निवेश क्षेत्र को नहीं त्याग सकता है। मिश्र का भू-राजनैतिक दृष्टि से भी अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए अत्यधिक महत्व है। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाज जहां मिश्र के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत हैं वहीं यह व्यापारिक व सैन्य दृष्टि से अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए भी महत्वपूर्ण है।

VI
विद्रोह का चरित्र

मिश्र के फरवरी 2011 जनविद्रोह को शासक वर्ग सहित जनता के व्यापक हिस्से द्वारा क्रांति की संज्ञा दी गई। 25 जनवरी को आधिकारिक तौर पर क्रांति दिवस की मान्यता दी जा चुकी है। सवाल यह उठता है कि क्या मिश्र के जनविद्रोह को क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार इसे क्रांति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। एक तो इस जनविद्रोह के बाद समाज में मौजूद उत्पादन सम्बंधों में कोई बदलाव नहीं आया और दूसरा राजसत्ता इस विद्रोह के पहले जिस वर्ग के हाथ में थी आज भी उसी के हाथ में है।

मिश्र के जनविद्रोह को क्रांति के रूप में मान्यता देने में मिश्र के शासक वर्ग और साम्राज्यवाद के विशेष हित व षड्यंत्र छिपे हुये हैं। इससे वह मिश्र के मजदूर वर्ग सहित उत्पीड़ित-शोषित तबकों के विद्रोही तेवरों को खत्म करने की साजिशें रचता रहा है। और अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही वह 'क्रांति' का श्रेय भी हासिल करना चाहता है। मिश्र की सेना तो इस 'क्रांति' की आधिकारिक प्रवक्ता बन गयी। मुर्सी के शासन के पतन में निभायी गयी उसकी भूमिका से मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से के लिए अल-सिसी जननायक बन चुके हैं। और अल-सिसी मिश्र की क्रांति के संरक्षक के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं।

कई बुद्धिजीवियों ने मिश्र की क्रांति को उत्तर आधुनिक क्रांति (Post modern revolution) की संज्ञा दी है। और इस बात की बेहद प्रशंसा की कि यह नेता विहीन क्रांति थी। एक आलेख कहता है,

> "मिश्र की क्रांति नेता विहीन (Leaderless) क्रांति का शास्त्रीय उदाहरण है। 2011 के प्रारम्भ में करीब एक करोड़ लोग मिश्र में होस्नी मुबारक की तानाशाही के खिलाफ आंदोलित हुए। वे न तो किसी एक विचारधारा से बंधे हुए थे और न वे किसी एक सांगठनिक मशीनरी के अंग थे।..." (Stanly Johny, Egypt; tragedy of a Post modern Revolution' Web edition EPW Aug 24, 2013,अनुवाद हमारा)

मिश्र के जनविद्रोह की यह उत्तर आधुनिक व्याख्या एकदम गलत है। इसे उत्तर आधुनिक क्रांति कहकर उत्तर आधुनिकतावादी अपनी दिवालिया विचारधारा के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मिश्र के जनविद्रोह को जबरदस्ती उत्तरआधुनिक सोच व ढांचे में ठूंसना है। मिश्र के जनविद्रोह को नियोजित व निर्देशित करने में मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर गैर सरकारी संगठनों के सांगठनिक ढांचे व तंत्र का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर गैर सरकारी संगठन पूंजीवादी विचारधारा के विभिन्न किस्मों के प्रति समर्पित रहे हैं। फरवरी 2011 के बाद के घटनाक्रम ने बहुत अच्छे ढंग से स्थापित भी किया है कि वे मिश्र के शासक वर्ग और साम्राज्यवाद की सुरक्षा पंक्तियों के हिस्से हैं।

मिश्र के जनविद्रोह में स्वतः स्फूर्तता का तत्व मूल में रहा है। यह मिश्र के समाज के गहराते अंतर्विरोधों व बढ़ते वर्ग संघर्ष का नतीजा रहा है। मिश्र के शासक वर्ग व साम्राज्यवाद ने इस जनविद्रोह को पहले कुचलने व इसमें सफल न होने पर इसे अपने हितों के अनुरूप दिशा देने व निर्देशित करने की हरचंद कोशिश की। इस जनविद्रोह का घटनाक्रम जिस ढंग व जिस दिशा में विकसित हुआ उसने अपने स्वतः स्फूर्तता के चरित्र के कारण शासक वर्ग व साम्राज्यवाद के सामने कई तरह की चुनौतियां पेश कीं और उसे एक के बाद एक कई कार्यवाहियां करनी पड़ी व छूटें देनी पड़ीं जो वह सामान्य हालात में कभी देने को तैयार नहीं होता। मिश्र के समाज में मजदूरों व अन्य मेहनतकशों के इस जनविद्रोह के फलस्वरूप जनवाद का विस्तार हुआ और इसने शासक वर्ग को संसदीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था को अपनाने को मजबूर किया है। अल-सिसी के नेतृत्व वाली सरकार का नागरिक मुखौटा पहनना, आपातकाल को

सीमित समय के लिए लगाना, नये संविधान का तेजी से मसौदा तैयार करना व चुनावों की घोषणा करने जैसी कार्यवाहियां मिश्र के मजदूर व अन्य मेहनतकशों के दबाव के कारण ही हो रही हैं।

सार रूप में देखा जाय तो मिश्र के जनविद्रोह का चरित्र मूलतः स्वतः स्फूर्त था। यह जनविद्रोह मूलतः जनवादी कार्यभारों को लेकर था। मजदूर वर्ग खासकर औद्योगिक मजदूर वर्ग 2011 के जनविद्रोह के काफी वर्ष पहले से मिश्र में इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था और यही वर्ग पूरे जन विद्रोह के काल में अपने संघर्षों से गति व निरन्तरता प्रदान कर रहा था। उसके पास अपनी पार्टी व नेतृत्व का अभाव था फिर भी वह मैदान में डटा रहा और अन्य वर्गों को जागृत व संघर्ष के मैदान में उतारता रहा।

VII
मिश्र का भविष्य

आज मिश्र संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। पिछले दो-तीन वर्षों में समाज में मूल संघर्ष जनवाद को लेकर रहा है। मिश्र के शासक वर्ग ने समाज को शोषित-उत्पीड़ित वर्गों-तबकों की जनवादी आकांक्षाओं को पूंजीवादी व्यवस्था में समेटने के लिए षड्यंत्रकारी ढंग से कई कदम उठाये हैं। अपने सार रूप में अब वह एक ऐसे संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ रहा है जिसका राजकीय धर्म इस्लाम होगा और जो कानूनों का निर्माण करने के लिए शरीयत का सहारा लेगा। और इस तरह से वह शासक वर्ग के एक हिस्से मुस्लिम ब्रदरहुड से सुलह समझौते करते हुए व अन्य इस्लामिक कट्टरपंथियों का इस तरह से पक्षपोषण करेगा कि वह एक भरोसेमंद सुरक्षा पंक्ति के रूप में बने रहें। मिश्र का शासक वर्ग मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हिस्से के प्रति लम्बे समय तक हमलावर नहीं रह सकता है। उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

शासक वर्ग जैसे ही अपने अंतर्विरोधों को एक हद तक हल करेगा और हालात पर काबू पा लेगा वह पुनः मजदूर वर्ग पर हमला बोलेगा। उसके संघर्षों को कुचलने व उनकी धार कुंद करने के लिए वह हर हथकण्डे को अपनायेगा और वस्तुतः वह अपना भी रहा है। संविधान की जो रूपरेखा तैयार की जा रही है उसमें इस बात का वह पूरा बंदोबस्त कर रहा है कि मजदूर वर्ग के जुझारूपन पर निर्णायक रूप से काबू पाया जाय। वह अपने तंत्र में मजदूर वर्ग की आर्थिक मांगों को तो एक स्थान दे सकता है परन्तु उसकी राजनैतिक मांगों व संघर्ष को कोई स्थान नहीं देना चाहता है।

मिश्र के वर्तमान जनविद्रोह को जिन कारकों ने जन्म दिया था वे क्योंकि आज भी वैसे ही बने हुए हैं अतः देर सबेर फिर मजदूर वर्ग सहित सभी शोषित-उत्पीड़ित वर्गों-तबकों के संघर्ष नये ढंग से फूट पड़ने लाजिमी हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का वर्तमान आर्थिक संकट मिश्र सहित पूरी दुनिया में एक के बाद एक नये जनसंघर्षों के फूट पड़ने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। इसलिए किसी भी देश के शासक वर्ग के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस बात का बंदोबस्त कर सके कि उनके यहां संघर्ष न फूटे। वे मिश्र के वर्तमान जनविद्रोह की तरह उसे निर्देशित, दिगभ्रमित व कुचलने की योजनाओं में लिप्त हैं। अतीत के अनुभवों से सीखकर शासक वर्ग ज्यादा सतर्क और धूर्त हो चुका है। परन्तु वह उन वस्तुगत नियमों का कुछ नहीं कर सकता है जो उसकी व्यवस्था को एक के बाद एक संकटों में धकेलते हैं। और उन्हीं वस्तुगत नियमों के वशीभूत होकर शोषित-उत्पीड़ित वर्ग और तबके उसे संघर्ष के मैदान में खींच लाते हैं। आज मिश्र के मजदूर वर्ग और अन्य शोषित-उत्पीड़ित तबकों को मिश्र के समाज में नेतृत्व देने के लिए एक सही क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का अभाव है। यद्यपि इस तरह की कई शक्तियां हैं जो समाजवाद और साम्यवाद की बातें करती हैं। आज की एकीकृत पूंजीवादी दुनिया में यह लगभग असम्भव है कि मिश्र का मजदूर वर्ग देर-सबेर सही क्रांतिकारी विचारधारा-मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा से अछूता रहे। और जितनी शीघ्र यह विचारधारा मजदूर वर्ग के अग्रणी व हिरावल तबकों के पास पथप्रदर्शक विचारधारा के रूप में पहुंचेगी उतनी शीघ्र मिश्र में एक ऐसी पार्टी सामने आयेगी जो मजदूर वर्ग के आधार पर खड़ी व बोल्शेविकीकृत होगी। एक ऐसी पार्टी ही मिश्र के समाज का सही विश्लेषण पेश कर उसकी रणनीतिक व रणकौशलात्मक लाइन का विकास कर सकती है। मिश्र के समाज में अधूरे छूटे जनवादी कार्यभारों को सम्बोधित कर सकती है और मिश्र के समाज को उस दिशा में ले जा सकती है जहां वह हर तरह के शोषण-उत्पीड़न से मुक्त हो।

VIII
मिश्र के जनविद्रोह का अंतर्राष्ट्रीय महत्व

आज की एकीकृत विश्व पूंजीवादी दुनिया में होने वाली घटनायें तुरन्त ही अपने पूरे वेग और प्रभाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। आधुनिक संचार तकनीक के जरिये किसी भी देश में होने वाली उथल-पुथल का असर विद्युतीय होता है। वह शासक वर्ग को भी चेताता व चौंकाता है तो शासित वर्ग की चेतना पर भी तुरन्त असर डालता है। मिश्र सहित पूरे अरब दुनिया में हुए बसंत के वज्रनाद की अनुगूंज पूरी दुनिया में महसूस की गई। 2011 में अरब दुनिया में फूटे जनसंघर्षों में सबसे ज्यादा प्रभावकारी व लम्बे समय तक चला संघर्ष मिश्र का ही है। इस जनसंघर्ष के कई सकारात्मक व नकारात्मक पहलू ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के सर्वहारा वर्ग के लिए कई जरूरी सबक पेश करते हैं।

मिश्र का जनविद्रोह किसी अर्द्ध सामंती समाज में नहीं फूटा बल्कि वह एक ऐसे समाज में फूटा जो एक पूंजीवादी समाज है और अरब क्षेत्र में सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वह ऐसे समाज में फूटा जहां नव उदारवादी नीतियां निर्ममतापूर्वक

लागू की गई। यह जनविद्रोह अपने चरित्र में शहरों में केन्द्रित था और इस रूप में यह बतला रहा है कि आधुनिक पूंजीवादी दुनिया में जनविद्रोह किस तरह से फूटेंगे। मिश्र के जनविद्रोह ने आम जनविद्रोह की झलक पेश कर दी है। इस जनविद्रोह के विकास और रूपों के गहराई से अध्ययन की मांग विश्व सर्वहारा आंदोलन से बनती है। मिश्र की राजधानी काहिरा के केन्द्र तहरीर चौक में उतरे जनसैलाब ने अपने शुरूआती दिनों में ही मिश्र की सेना व पुलिस को भारी उलझन में डाल दिया था। यह एक तरह से भावी जनक्रांति की रिहर्सल थी। और इस रिहर्सल ने विश्व सर्वहारा आंदोलन खासकर तीसरी दुनिया के सर्वहारा वर्ग के लिए उन घटनाओं व दृश्यों को पेश कर दिया जो कल उनके समाजों में भी घटित हो सकते हैं।

मिश्र के जनविद्रोह जिसमें मजदूर वर्ग सहित अन्य वर्गों-तबकों की जनवादी इच्छायें-आकांक्षायें अभिव्यक्त हो रही थी वह कमोबेश तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में जनवाद के अधूरे छूटे कार्यभारों की अभिव्यक्तियां हैं। परन्तु मिश्र के सर्वहारा वर्ग के आर्थिक संघर्षों से जो राजनीतिक मांग अभिव्यक्त होती है वह मिश्र के वर्तमान पूंजीवादी ढांचे के स्थान पर समाजवादी समाज के गठन के प्रश्न को मुखरता से पेश करती है। इस तरह से मिश्र के जनविद्रोह से सर्वहारा वर्ग के लिए जनवादी कार्यभारों को सम्बोधित करते हुए समाजवादी क्रांति को सर्वहारा वर्ग की कार्यसूची में लाने और उनके अंतरसम्बधों को सही ढंग से रेखांकित करने का कार्यभार प्रस्तुत होता है। अर्थात अपने-अपने देशों में सही क्रांतिकारी कार्यक्रम को पेश करने और उसे व्यवहार में उतारने की जरूरत सामने आती है।

मिश्र के जनविद्रोह के समय और आज निम्न बुर्जुआ राष्ट्रवाद (अरब राष्ट्रवाद) का एक तत्व दिखायी देता है परन्तु इसने दिखला दिया है कि अब इतिहास में इस विचारधारा का कोई खास महत्व नहीं रह गया है। यह अब लोकप्रिय नारों को गढ़ने और अपने पीछे सर्वहारा वर्ग को लामबंद करने में अक्षम हो गया है। हालांकि यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि बुर्जुआ वर्ग अपने संकट के समय राष्ट्रवाद के नारे का इस्तेमाल हमेशा करता है और इस नारे की ओट लेकर वह मजदूर वर्ग सहित शोषित-उत्पीड़ित तबकों के जनसंघर्षों पर खुला-छिपा हमला बोलता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग के लिए आवश्यक है कि वह बुर्जुआ वर्ग के राष्ट्रवाद के नारे की आड़ में छुपे घृणित हितों का पर्दाफाश करे और उसके द्वारा राष्ट्रीय जनवादी कार्यभारों के सिलसिले में साम्राज्यवाद और सामंती प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ किये गये गठजोड़ का पर्दाफाश करे। मिश्र में मुर्सी व अब अल-सिसी बुर्जुआ राष्ट्रवाद का दामन पकड़कर मिश्र के जनसंघर्षों की धार को कुंद करने में लगे रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के संकट में घिरने पर राष्ट्रवाद बुर्जुआ वर्ग का कारगर हथियार बनता रहा है।

मुस्लिम ब्रदरहुड ने अपने एक वर्ष के शासन के दौरान यह दिखाया कि वह कैसे आर्थिक नीतियों को तेजी से लागू करने व समाज में मौजूद पिछड़ी मूल्य-मान्यताओं सहित धार्मिक कूपमंडूकता का इस्तेमाल कर किस तरह से समाज को पीछे धकेल सकता है। मुस्लिम ब्रदरहुड मिश्र के शासक वर्ग सहित साम्राज्यवाद के हितों के लिए एक सुरक्षा पंक्ति के रूप में सदैव मौजूद रहा है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति का सामना पूरी दुनिया के सर्वहारा वर्ग को करना पड़ सकता है। ऐसी ही चुनौतियां अपने भिन्न रंग रूप में उनके समाजों में भी मौजूद हैं। इसलिए सर्वहारा वर्ग के लिए आवश्यक है कि वह धार्मिक कूपमंडूकता में लिपटे प्रतिक्रियावादी तत्वों का निरन्तर पर्दाफाश करे। अपनी पांतों को इसके प्रभाव से मुक्त करे। मध्ययुगीन धार्मिक मूल्य मान्यताओं के खिलाफ अनवरत संघर्ष चलाये। इन तत्वों के द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्यों और विशेषकर आपदाओं के समय निभायी जाने वाली भूमिका के पीछे छिपे हुए घृणित मंसूबों को उजागर करे। इसी तरह की बातें गैर सरकारी संगठनों के द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका के बारे में भी लागू होती हैं।

मिश्र के जनविद्रोह के समय साम्राज्यवाद की भूमिका विश्व सर्वहारा वर्ग के सामने इस बात की चुनौती को समझने का अवसर प्रदान करती है कि कैसे साम्राज्यवाद किसी देश विशेष में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ढंग से हस्तक्षेप कर किसी जनसंघर्ष की धार को कुंद कर सकता है। अपने मीडिया व गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क के जरिये कैसे जनसंघर्षों को भ्रमित और पूंजीवादी व्यवस्था के दायरे में बांध कर रख सकता है।

मिश्र के जनसंघर्ष में नयी संचार तकनीक की क्षमता और सीमा दोनों ही बराबर रूप से सामने आयी। एक तरफ जहां इसने शोषित-उत्पीड़ित तबकों को संघर्ष के लिए प्रेरित, आंदोलित व संगठित करने में सकारात्मक भूमिका निभायी वहीं इसने बाद के समय में शासक वर्ग को बहुत आसानी से विद्रोह को कुचलने के लिए आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध करा दीं। होस्नी मुबारक के द्वारा इण्टरनेट पर प्रतिबंध लगाते ही उस पर निर्भर लोग निहत्थे हो गये। विश्व सर्वहारा के वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि जहां वह इस तकनीक व तंत्र का इस्तेमाल करे वहीं वह इस बात का पुख्ता बंदोबस्त करे कि उसका संगठन व योजनायें दुश्मन वर्ग को उपलब्ध न हो पायें। परम्परागत तौर-तरीकों को तिलांजलि देकर मात्र आधुनिक संचार तकनीक के साधनों पर निर्भरता बहुत आत्मघाती साबित हो सकती है।

मिश्र के जनविद्रोह का सर्वोपरि सबक जैसा कि इस लेख में बार-बार स्थापित किया गया है यह है कि क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित सर्वहारा वर्ग की पार्टी की आवश्यकता है। बिना पार्टी के सर्वहारा वर्ग के संघर्ष वे चाहे कितने भी जुझारू क्यों न हों एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं बुर्जुआ वर्ग के लिए वास्तविक चुनौती नहीं बन सकते हैं। मिश्र के बुर्जुआ वर्ग ने नासिर के जमाने से ही यह पूरी कोशिश की है कि सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में ही न आ सके। हाल के दिनों में जनविद्रोह के दौरान यद्यपि सर्वहारा वर्ग के बीच विभिन्न वाम नाम धारी पार्टियां सक्रिय रही हैं परन्तु उनकी नकारात्मक भूमिका ने भी क्रांतिकारी विचारधारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा पर आधारित पार्टी की ही आवश्यकता को पुरजोर रूप से स्थापित किया है।

मिश्र के समाज में 2011-13 के दौरान जो सामाजिक उथल-पुथल मची यदि उसमें सर्वहारा वर्ग की पार्टी मौजूद होती तो वह इस जनविद्रोह को क्रांति में तब्दील करने की ओर ले जा सकती थी। वह वस्तुगत परिस्थिति मिश्र के समाज में मौजूद हो चुकी थी जो क्रांति के लिए आवश्यक होती है परन्तु पार्टी के अभाव में ऐसी परिस्थितियां पुनः उत्पन्न होने पर सर्वहारा वर्ग समाज को क्रांति की ओर नहीं ले जा सकता है।

आज दुनिया की जो स्थिति है उसमें मिश्र की तरह के जनविद्रोहों के फूट पड़ने की अधिकाधिक सम्भावना पैदा होती जा रही है। ऐसी स्थिति में सर्वहारा वर्ग की पार्टी की आवश्यकता और उनके दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को एकसूत्र में बांधने और विश्व क्रांति को नेतृत्व देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की आवश्यकता भी तीव्रता से सामने आ रही है।

अंत में, मिश्र के सर्वहारा सहित विश्व सर्वहारा वर्ग को मजदूर वर्ग के महान शिक्षक फ्रेडरिक एंगेल्स की निम्न पंक्तियों पर गौर करना चाहिये,

> "... ... ... उस अंधविश्वास का जमाना कभी लद चुका है जो चंद आंदोलनकारियों की दुर्भावना को क्रांतियों का कारण बताया करता था। अब हरेक को पता है कि जहां कहीं क्रांतिकारी उथल-पुथल होती है, वहां पार्श्वभूमि में कोई न कोई सामाजिक आवश्यकता होती है जिसकी जीर्ण पड़ चुके संस्थान पूर्ति नहीं होने देते। हो सकता है कि यह आवश्यकता अभी इतने जोरदार ढंग से, इतने व्यापक रूप से अनुभव न की जाती हो जो तात्कालिक सफलता सुनिश्चित कर सके, परन्तु बलपूर्वक दमन की हर कोशिश उसे तब तक अधिकाधिक सशक्त ढंग से ऊपर लाती रहेगी जब तक वह आवश्यकता अपने बंधनों को तोड़ नहीं देती। इसलिए यदि हम पिट जाते हैं तो हमारे पास इसके अलावा करने को और कुछ नहीं रह जाता कि फिर नये सिरे से काम शुरू करें।" (फ्रेडरिक एंगेल्स,'जर्मनी में क्रांति तथा प्रतिक्रांति' पृष्ठ - 8, पैरा-2, का. मार्क्स- फ्रे. एंगेल्स की संकलित रचनाएं, तीन खण्डों में, खण्ड-1, भाग-2, प्र. प्रकाशन, मास्को)

■■■